बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 129

सीमित संभावनाएं

संयुक्त राष्ट्र ने गत सप्ताह विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में व्यापक तौर पर वैश्विक जनांकिकी के भविष्य की राह समेत कई अनुमान जताए गए हैं तथा चुनिंदा देशों और क्षेत्रों को लेकर भविष्यवाणी की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया की आबादी में इजाफा जारी रहेगा और 2080 के दशक के आरंभ तक दुनिया की आबादी 10 अरब का आंकड़ा पार कर जाएगी। उसके बाद आबादी में गिरावट का सिलसिला आरंभ होगा। यह समग्र रुझान क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय अंतर को छिपा लेता है। इस अवधि में बाद के वर्षों में आबादी में होने वाली वृद्धि का अधिकांश भाग अफ्रीका महाद्वीप से आएगा, खासतौर पर सब-सहारा अफ्रीका से। इनमें से कई देश मसलन सोमालिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो (डीआरसी) फिलहाल आर्थिक रूप से पिछड़े और राजनीतिक रूप से अस्थिर हैं। उनमें से कुछ देश मसलन डीआरसी आदि में भरपूर प्राकृतिक संसाधन भी हैं जिनका मूल्य आने वाले दशकों में बढ़ेगा। इन देशों में युवा आबादी भी होगी और संसाधनों को लेकर प्रतिस्पर्धा भी होगी। जाहिर है भविष्य में ये वैश्विक और भूराजनीतिक दृष्टि से अहम होंगे।

वैश्विक जनसंख्या संभावना रिपोर्ट से यह संकेत भी मिलता है कि निकट भविष्य में भारत की आबादी चीन से अधिक रहने वाली है। बहरहाल इसका अनुमान है कि पाकिस्तान की आबादी का बढ़ना भी जारी रहेगा और 39 करोड़ की आबादी के साथ वह अमेरिका से आगे निकल जाएगा। यह बात भारत और विश्व के लिए महत्त्वपूर्ण है। यह देखना शेष है कि भारत की पाकिस्तान को अलग-थलग रखने और अनदेखा करने की नीति क्या तब भी टिकाऊ होगी जब वह दुनिया का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला मुल्क बन जाएगा? रिपोर्ट के अनुसार भारत की आबादी में 2062 के बाद कमी आनी शुरू हो जाएगी यानी वैश्विक जनसंख्या के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचने के करीब दो दशक पहले उसकी आबादी घटने लगेगी।

इससे भी अहम बात शायद यह है कि देश की समस्त आबादी में गिरावट शुरू होने के करीब एक दशक पहले ही उसकी श्रम योग्य आयु की आबादी के बढ़ने की गति आम आबादी की तुलना में कहीं अधिक तेजी से धीमी होगी। निर्भरता अनुपात की बात करें तो 15 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या में इजाफा होगा। बढ़ती और उच्च निर्भरता अनुपात वाले देश आमतौर पर उस सीमा से गुजर चुके हैं जहां वे प्रति व्यक्ति आय में इजाफा कर सकते थे। भारत के लिए इसके आर्थिक और नीतिगत निहितार्थ स्पष्ट हैं। उसके पास समृद्ध होने के लिए तीन दशक हैं। अगर हम इस अवधि का समझदारी से इस्तेमाल नहीं कर पाए तो मध्य आय स्तर में उलझ सकते हैं। ऐसे में वह जनसंख्या उत्पादकता में असाधारण वृद्धि करने में भी नाकाम रहेगा।

जो लोग 2054 में श्रम शक्ति में सबसे बुजुर्ग होंगे वे इस समय रोजगार की तलाश में हैं। अल्पशिक्षित युवाओं के सरकारी नौकरी की तलाश में कतार में लगे होना नीति निर्माताओं के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। अगली सदी में तथा उसके बाद देश का भविष्य इन्हीं लोगों पर निर्भर करेगा। क्या उनके पास वह कौशल है कि वे देश को उच्च आय के स्तर पर ले जा सकें? इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक नहीं लगता। ऐसे में कौशल उन्नयन सरकार की पहली प्राथमिकता होना चाहिए। केवल रोजगार निर्माण करना उस आबादी के लिए पर्याप्त नहीं है जो अवसरों का लाभ लेने का कौशल नहीं रखती। उच्च और जीवनपर्यंत शिक्षा के विविध मॉडलों को आजमाना चाहिए। व्यावसायिक प्रशिक्षण का विस्तार होना चाहिए। भारत के जनांकिकीय लाभ का वक्त हाथ से फिसल रहा है। उम्रदराज होने की प्रक्रिया को पलटा नहीं जा सकता है और भारत को अगले तीन दशक में अपनी जनांकिकी का लाभ लेना चाहिए।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुद्रीकरण और हम

बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत के मूल्यांकन प्रीमियम से लाभ हासिल कर रही हैं। परंतु इस दौरान हमें भी पर्याप्त सावधानी बरतनी होगी। बता रहे हैं आकाश प्रकाश

मैं कई दशकों से भारतीय बाजारों में निवेश कर रहा हूं। इस दौरान, हमने वैश्विक कंपनियों को भारतीय परिचालन में निरंतर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते देखा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने लगातार ऐसे अवसरों की तलाश की है जिनकी बदौलत वे अपना आर्थिक स्वामित्व बढ़ा सकें या अपनी भारतीय अनुषंगी कंपनियों को पूरी तरह निजी बना सकें। इसके लिए वे निजी कंपनियों के साथ विलय, शेयरों की पुनर्खरीद या उनका प्राथमिकता पर आवंटन कराने जैसे कदम उठाती हैं। भारतीय कारोबार पर पूरे मालिकाने के लक्ष्य को लेकर जितना अधिक दांव लगाया जाए उतना ही बेहतर होता है। कई कंपनियों ने उस समय प्रचलित बाजार मूल्य से अधिक प्रीमियम पर अपने दांव बढ़ाए जो स्पष्ट रूप से यह संकेत देते रहा था कि बाजार उनके भारतीय कारोबार की दीर्घकालिक संभावनाओं को कम करके आंक रहे थे।

विगत 12 महीनों में यह रुझान बदला है। अब कई ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जिन्होंने अपनी हिस्सेदारी का मुद्रीकरण किया है और वे अपने भारतीय परिचालन में अपनी आंशिक हिस्सेदारी बेच रहे हैं। व्हर्लपूल, टिमकेन और जेडएफ उन वैश्विक बहुराष्ट्रीय समूहों का उदाहरण हैं जो अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं और उच्च मूल्यांकन का मुद्रीकरण कर रहे हैं। ह्युंडै मोटर्स मूल्यांकन का लाभ उठाने और अपनी भारतीय अनुषंगी को सूचीबद्ध करने वाली सबसे बड़ी वैश्विक कंपनी के रूप में सामने आई है। ह्युंडै तीन अरब डॉलर से अधिक राशि जुटा सकती है जो भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश होगी। व्हर्लपूल ने करीब 50 करोड़ डॉलर जुटाए। इसके लिए उसने अपनी हिस्सेदारी 75 फीसदी से कम करके 51 फीसदी कर ली। यह पैसा वैश्विक बैलेंस शीट के नकदीकरण के लिए जुटाई जा रही है या शायद इलेक्ट्रिक वाहन जैसे नए क्षेत्रों में निवेश करने के लिए। बैंकरों के मुताबिक यह रुझान अभी शुरू होता नजर आ रहा है और शायद आने वाले महीनों में और बहुराष्ट्रीय कंपनियां मुद्रीकरण करती नजर आएं। बड़े भारतीय कारोबार वाली कई अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियां ह्युंडै का अनुसरण कर सकती हैं। जब आप अपने मूल देश के पांच गुना के मूल्य आय चर की तुलना में भारत में 20-25 गुना मूल्य आय चर पर सूचीबद्ध हो सकते हैं और आपको इक्विटी पूंजी की आवश्यकता हो तो आकर्षण स्वाभाविक है। आप स्थानीय कारोबार पर नियंत्रण रखते हुए भी भारी पूंजी जुटा सकते हैं।

यह रुझान अच्छा है या चिंतित करने वाला? यह भारत के पूंजी बाजारों की परिपक्वता और उनके आकार का स्पष्ट संकेत है। भारत का बाजार पूंजीकरण 5 लाख करोड़ डॉलर से अधिक का है और हम दुनिया में चौथे स्थान पर हैं। औसत दैनिक कारोबार का आकार अब ह्यॉन्गकॉन्ग से अधिक हो चुका है। महज पांच साल से भी कम पहले एमएससीआई उभरते बाजार सूचकांक में भारत का भार (वेटिंग) 10 फीसदी और चीन का करीब 40 फीसदी था। आज भारत का भार बढ़कर करीब 20 फीसदी है जो दूसरा सबसे अधिक भार है। चीन 24 फीसदी के साथ सबसे आगे है। हमारा पूंजी बाजार उन निजी बाजारों में शामिल है जो अरबों के इश्यू का समर्थन करते हैं।

हमारा जीडीपी चार लाख करोड़ डॉलर का है और पारिवारिक बचत की दर 20 फीसदी है। यह बचत भारतीय संपत्तियों में है और तेजी से शेयरों में जा रही है। ऐसे में भारत सूचीबद्धता के लिए अनुकूल जगह है। विशुद्ध आधार पर भी यह बहुत आकर्षक और बढ़ती बचत है।

ऐसी दुनिया में जहां निवेशक सीमित आईपीओ बाजार की शिकायत करते हैं और सूचीबद्धता की कमी की बात कहते हैं, वहां भारतीय बाजार नई सूचीबद्धता के प्रति खुलेपन की दृष्टि से अलग दिखते हैं। यहां तमाम क्षेत्रों और उद्योगों की कंपनियां सूचीबद्ध हो सकती हैं। हमें कई आईपीओ और द्वितीयक बाजार देखने को मिल रहे हैं। यह जीवंतता स्टार्टअप के माहौल को भी मजबूत करती है। मिसाल के तौर पर वेंचर कैपिटल की पूंजी बाजार से निकलने की क्षमता पर सवाल नहीं किया जाता है।

भारत दुनिया के उन चुनिंदा बाजारों में से एक है जहां पारंपरिक कार कंपनियां दो अंकों वाले चर में सूचीबद्ध हो सकती हैं और अरबों डॉलर की राशि जुटा सकती हैं। इसी तरह घरेलू उपकरण बनाने वाली किसी कंपनी या वाहन कलपुर्जा कंपनी के लिए पश्चिम में 50 करोड़ डॉलर जुटाने की कोशिश की अपनी मुश्किलें हैं। पुराने कारोबारी मॉडलों के लिए भारत उन चुनिंदा बाजारों में से एक हो सकता है जहां उचित मूल्यांकन पर सूचीबद्धता हो सकती है। विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय परिसंपत्तियां वैश्विक कंपनियों की तुलना में महत्त्वपूर्ण मूल्यांकन प्रीमियम पर कारोबार कर रही हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां मूल्यांकन के अंतर्विरोध को देखते हुए अलग-अलग वृद्धि और मूल्यांकन अपेक्षाओं का लाभ उठा रही हैं। वे भारत के प्रीमियम का उपयोग अपने लाभ के लिए कर रही हैं।

इक्विटी में बढ़ती आवक के जारी रहने की उम्मीद को देखते हुए आईपीओ पाइपलाइन वास्तव में सकारात्मक है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि इक्विटी की मांग पर्याप्त आपूर्ति के जरिये पूरी हो। मजबूत आईपीओ बाजार यह सुनिश्चित करता है कि इक्विटी में आने वाले पैसे का इस्तेमाल वित्तीय कारोबार के विस्तार में किया जा सके, बजाय कि केवल द्वितीयक कीमतों में इजाफा करने के। नियामक को आपूर्ति की गुणवत्ता तथा वास्तविकता सुनिश्चित करना चाहिए। यदि बुलबुले जैसी स्थिति बनती है तो पूंजी का गलत आवंटन होता है और इससे बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। अब जबकि वैश्विक कंपनियां भारत में प्रीमियम चर का लाभ मुद्रीकरण के लिए कर रही हैं, भारतीय कंपनियां भी रणनीतिक उद्देश्य से ऐसे चरों का लाभ ले सकती हैं। वे विदेशों में द्वितीयक सूचीबद्धता तैयार कर सकती हैं जो स्थानीय कीमतों पर कारोबार कर सकती है और मुद्रा का इस्तेमाल वैश्विक परिसंपत्तियों या प्रतिभाओं को जुटाने के लिए कर सकती हैं।

यद्यपि हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि कुछ कारणों से रुकने की भी जरूरत है। अगर सबसे बड़ा शेयरधारक बेच रहा है और अपनी मर्जी से बेच रहा है तो हम क्यों खरीद रहे हैं? क्या यह भेदिया बिकवाली के समान नहीं है? आखिर कंपनी की दीर्घकालिक संभावनाओं के बारे में मुझे क्या पता है जो बहुराष्ट्रीय बिक्रेता को नहीं पता है? सामान्य तौर पर प्रमुख अंशधारक के अतिरिक्त किसी के पास दीर्घकालिक परिदृश्य की बेहतर समझ नहीं होती है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमेशा हिस्सेदारी बढ़ाने का प्रयास करती हैं। आज बदलाव क्यों? क्या मूल्यांकन पूरी तरह असंगत है? क्या यह मुद्रीकरण पूंजी का उनका सबसे सस्ता जरिया है? क्या आज भारतीय कारोबारों का आकार ऐसा है कि वैश्विक रूप से प्रासंगिक मुद्रीकरण की घटनाएं भारत में हों? क्या बाजार दीर्घकालिक वृद्धि संभावनाओं को लेकर अधिक आशावादी है? वजह चाहे जो भी हो यह एक और आंकड़ा है जो बताता है कि आज भारत में मूल्यांकन कितना ऊंचा है।

यह तो स्पष्ट है कि हम तेजी के बाजार में हैं। देखना यह होगा कि ये सिलसिला कितना लंबा चलता है। एक बात स्पष्ट है कि जब तक घरेलू निवेशकों का भरोसा डांवाडोल नहीं होता है तब तक हमारे बाजारों में बड़ी गिरावट नहीं आने वाली है। फिलहाल तो ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा है।

(लेखक अमांसा कैपिटल से संबद्ध हैं)

खनिज क्षेत्र में तोड़ना होगा एकाधिकार

महत्त्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्त्वों का महत्त्व 21वीं सदी में बहुत अधिक बढ़ गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी), रक्षा, अंतरिक्ष और चिकित्सा उपकरणों में उपयोग की दृष्टि से आज ये अर्थव्यवस्था के केंद्र बिंदु में हैं। उदाहरण के लिए अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस और बढ़ने से रोकने के लिए अपनाए जा रहे उपायों के तहत नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी वर्ष 2050 तक 91 प्रतिशत तक बढ़ानी होगी। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर सिलिकन, चांदी, लीथियम जैसे खनिजों तथा नियोडिमियम और डिस्प्रोजियम जैसे दुर्लभ मृदा तत्त्वों की आवश्यकता होगी। इन्हें और ग्रेफाइट, मैंगनीज, कोबाल्ट और निकल जैसे खनिजों को महत्त्वपूर्ण खनिजों के रूप में रखा गया है।

महत्त्वपूर्ण खनिज अब रणनीतिक संपत्ति बन गए हैं और इन्हें भू-राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये खनिज कुछ ही देशों में अधिक पाए जाते हैं और चीन का इस मामले में प्रभुत्व कायम है, जहां वैश्विक भंडारों का 50 प्रतिशत डिस्प्रोजियम, 50 प्रतिशत नियोडिमियम और 65 प्रतिशत ग्रेफाइट मौजूद है।

अफ्रीका, लातिन अमेरिका, मध्य एशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ मुख्य रूप से बेल्ट ऐंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) जैसी पहलों के माध्यम से चीन ने अपने खनिज प्रभुत्व की दीवार को बहुत अधिक मजबूत बना लिया है। घाना, गिनी, नाइजर, सिएरा लियोन और माली जैसे देशों में खनिज अन्वेषण तथा प्रसंस्करण में 1.3 अरब डॉलर बीआरआई निवेश कर चीन ने एक तरह से बॉक्साइट एवं लीथियम के भंडारों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है।

चीन विश्व की खनिज प्रसंस्करण राजधानी बन गया है और इस क्षेत्र में इसका एकाधिकार कायम है। विश्व के ग्रेफाइट (80%), डिस्प्रोजियम (100%), मैंगनीज (93%) और नियोडिमियम (88%) पर चीन का नियंत्रण है। चीन के इस औद्योगिक कौशल से उसकी प्रसंस्करण लागत काफी घट गई है। खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला पर चीन का कब्जा और ज्यादा मजबूत हो गया है।

महत्त्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला पर एका धिकार से वैश्विक स्तर पर अनेक चिंताएं पैदा होती हैं। एक क्षेत्रीय विवाद के चलते चीन ने वर्ष 2010 में जापान के लिए दुर्लभ मृदा तत्त्वों का निर्यात रोक दिया था। हाल ही में जब अमेरिका ने चीन को सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया तो बदले में उसने अक्टूबर 2022 में जर्मेनियम और गैलियम का निर्यात अगस्त 2023 से रोकने का ऐलान कर दिया। ये दोनों चीजें सेमीकंडक्टर विनिर्माण के लिए बहुत आवश्यक होती हैं, जिसके उत्पादन में चीन की वैश्विक हिस्सेदारी क्रमशः 60 और 80 फीसदी है।

अजय कुमार

दक्षिणी चीन सागर को लेकर चीन और अमेरिका के बीच चले आ रहे तनाव के बीच चीन ने अमेरिका को सिंथेटिक ग्रेफाइट ग्रेड का निर्यात भी रोक दिया, जो रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण होता है। इसके उत्पादन में भी चीन अग्रणी बना हुआ है। महत्त्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्त्वों की कीमतों एवं आपूर्ति को संतुलित करने के लिए अन्य भू-राजनीतिक कदम उठाने की आवश्यकता है। इसमें ओपेक जैसा संगठन बनाना भी एक बेहतर कदम हो सकता है। चीन जैसे देशों के प्रभुत्व को तोड़ने के लिए अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने महत्त्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति के लिए स्थानीय स्तर पर संभावनाएं तलाशने के साथ-साथ मित्र राष्ट्रों पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। हालांकि उनके लिए इस तरफ मुड़ना काफी महंगा साबित हो रहा है।

पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान महत्त्वपूर्ण खनिजों को लेकर साझेदारी का मुद्दा प्रमुख एजेंडे में शामिल था। अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन और 13 अन्य देशों के साथ खनिज सुरक्षा साझेदारी की शुरुआत 2022 में की थी। भारत भी 2023 में इस पहल का हिस्सा बन गया।

भारत ने 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। ऐसे में उसे उत्सर्जन कम करने वाले अधिक उपाय अपनाने होंगे। चूंकि भारत इन खनिजों विशेषकर कोबाल्ट, निकल एवं लीथियम के 100 प्रतिशत, तांबा एवं इसके तत्त्वों के 93 प्रतिशत आयात पर निर्भर है।

केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भारी खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। अंडमान सागर और लक्षद्वीप सागर के साथ पॉलिमेटालिक फेरोमैंगनीज नोडल्स और क्रस्ट के भी पर्याप्त भंडार मौजूद हैं। भारत के पास 21 करोड़ टन ग्रेफाइट और 66.5 करोड़ टन इल्मेनाइट एवं रुटाइल के भंडार मौजूद हैं, परंतु इनका उत्पादन बहुत कम हो रहा है। इसमें भी ज्यादातर का कच्चे माल के रूप में ही निर्यात कर दिया जाता है। थोक खनिजों पर सरकार का अधिक जोर होने के चलते बहुत से महत्त्वपूर्ण खनिज ऐसे हैं, जिन पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। खनिजों की जितनी भी खोजें हो रही हैं, वे केवल सरकारी क्षेत्र की कंपनियां ही कर रही हैं, इस कारण इस क्षेत्र में निवेश भी नहीं आ रहा।

वैसे सरकार द्वारा हाल के दिनों में उठाए गए कदम काफी आशाजनक प्रतीत होते हैं। सरकार ने 30 खनिजों को महत्त्वपूर्ण खनिजों के रूप में चिह्नित करते हुए उनके अन्वेषण का काम अपने हाथ में ले लिया है।

सरकार ने वर्ष 2019 में इस क्षेत्र में 100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की इजाजत दे दी थी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने गहराई में दबे खनिजों के अन्वेषण के लिए लगभग 250 परियोजनाएं शुरू की हैं। संबंधित कानून में पिछले साल किए गए संशोधन के बाद नीलामी के जरिये इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की कंपनियों के रास्ते खुल गए हैं।

पूर्व में जिन खनिजों को परमाणु की श्रेणी में रखा गया था, उन्हें पुनः वर्गीकृत किया गया है, ताकि खनन में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। नवंबर 2023 में शुरू की गई तीन लीथियम ब्लॉकों और दुर्लभ मृदा धातुओं की नीलामी पूरी हो चुकी है। अपतटीय ब्लॉक भी नीलामी के लिए रखे गए हैं, जिससे नए अवसरों के द्वार खुलेंगे तथा स्टार्टअप दुनिया ने इस चुनौती से सफलतापूर्वक निपटने के लिए नई उन्नत तकनीक अपनानी शुरू कर दी हैं। ऑटोमोटिव, अंतरिक्ष, रक्षा, सेमीकंडक्टर एवं नवीकरणीय ऊर्जा के लिए कुछ खास खनिजों के भंडारण निरक्षण के दायरे में हैं।

भारत दूसरे देशों के साथ समझौते कर रहा है। खानजी बिदेश इंडिया ने सभी पांच ब्लॉकों में लीथियम अन्वेषण के लिए अर्जेंटीना के साथ हाथ मिलाया है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया में लीथियम और कोबाल्ट ब्लॉकों के लिए बातचीत चल रही है।

अफ्रीका के भरोसेमंद साथी समझे जाने वाले भारत को वहां प्रसंस्करण एवं सज्जीकरण सुविधाओं में निवेश करना चाहिए, ताकि स्थानीय अर्थव्यवस्था और द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत हों। अंतरराष्ट्रीय पहलों का फायदा उठाते हुए सरकार को निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी से इस क्षेत्र का ज्यादा से ज्यादा दोहन करना चाहिए। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत को अपनी खनिज प्रसंस्करण सुविधाओं का विस्तार करना चाहिए।

भारत को इस मामले में इंडोनेशिया की सफलता से कुछ सबक सीखना चाहिए, जो निकल खनन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन कर उभरा है। आज घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे माल तक उसकी पहुंच है। तेल परिशोधन की तरह ही भारत ली थियम शोधन और महत्त्वपूर्ण खनिजों को लेकर उभरने वाली अड़चनों को दूर करने के मामले में अग्रणी देश बन सकता है। इस लक्ष्य को हासिल करने, वैश्विक जरूरतों को पूरा करने एवं पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए प्रोत्साहन आधारित योजना (पीएलआई) लागू की जानी चाहिए।

(लेखक आईआईटी कानपुर में विजिटिंग प्रोफेसर एवं भारत के पूर्व रक्षा सचिव हैं)

आपका पक्ष

किसानों की मांगों का जल्द निकले हल

उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा सरकार से अंबाला के पास शंभू सीमा पर लगाए अवरोधकों को हटाने और वहां यातायात फिर से शुरू करने को कहा है। अदालत का यह भी कहना है कि कोई भी सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग को स्थायी रूप से नहीं रोक सकती, कारण सरकार का काम है यातायात को नियंत्रित करना उसे रोकना नहीं है। सरकार को डर है कि अगर उसने यातायात शुरू किया तो पंजाब के किसान एक बार फिर दिल्ली की ओर कूच कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर हरियाणा सरकार के लिए कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालना काफी कठिन हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा कारण यह भी है कि किसान अपनी मांगों के लिए लंबे समय से इस क्षेत्र में हड़ताल पर हैं एवं न केवल शंभू बॉर्डर बल्कि खनौती बॉर्डर पर ये सब धरना देकर बैठे हुए हैं। इन सब का आगे चलकर दिल्ली जाकर प्रदर्शन करने का भी इरादा है। ये सब किसान एक लंबे समय से एमएसपी एवं कई अन्य मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। अब राजग सरकार एक बार फिर सत्ता में आई है एवं नए कृषि मंत्री शिवराज चौहान से सभी की यही अपेक्षा है कि वह किसानों की जरूरी एवं महत्त्वपूर्ण मांगों का हल निकालने का शीघ्र अति शीघ्र प्रयास अवश्य करें ताकि एक बार फिर स्थिति फिर आगे चलकर बिगड़ न सके।

मनमोहन राजावत, शाजापुर

किसान अपनी मांगों के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। केंद्र सरकार को भी अब जल्द से जल्द उनका हल निकालना चाहिए

संतुलित बजट की अपेक्षा

बजट में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखते हुए किसानों और बेरोजगारों पर विशेष ध्यान देना अपेक्षित है। निरंतर बढ़ती महंगाई से राहत पाना आम नागरिक की प्राथमिक आवश्यकता है। अनावश्यक सरकारी खर्च नियंत्रित कर आयकर और मानक कटौती में राहत दी जाए। बजट का स्वरूप इतना संतुलित होना चाहिए कि महंगाई का बोझ कम होने के साथ ही बजट घाटा भी नहीं बढ़े।

रमेशचंद्र कर्नावट, उज्जैन, मप्र

करों में राहत मिले, मुफ्त रेवड़ी बंद हो

मुफ्त रेवड़ी बंद होने से जनधन का सदुपयोग देश के विकास में हो सकेगा और सुविधाएं भी बढ़ेंगी। करों में राहत देने से आम लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी। साथ ही बचत होने से क्रयशक्ति बढ़ेगी। जिससे अन्य जरूरी वस्तुओं की बिक्री भी बढ़ेगी और उत्पादन बढ़ेगा। करों में छूट देकर मध्यमवर्ग को सरकार राहत पहुंचाए। बेरोजगारी दूर करने के उपाय हों। शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती हों। इनके लिए बजट में उचित कदम उठाए जाने चाहिए।

शकुंतला महेश नेनावा, इंदौर, मप्र

बजट में सभी वर्गों का रखना होगा ख्याल

आम बजट सर्वस्पर्शी और विकास वादी होना चाहिए। योग्य युवाओं को रोजगार देने के उपाय के साथ ही शिक्षा और गृह ऋण कम दरों पर होने चाहिए। 70 वर्ष से ज्यादा की आयु वाले लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ इसी बजट से होना चाहिए। जिस तरह आयकर में बीमा की किस्त में छूट की धारा होती है, उसी तरह आयकर में महंगाई की छूट की धारा लागू करनी चाहिए और आयकर की सीमा बढ़ानी चाहिए।

डॉ. उमेश मित्तल, सहारनपुर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफ़र मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

सोमवार को भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ की 'बहुड़ा यात्रा' या वापसी यात्रा शुरू हुई। श्रद्धालुओं ने भगवान बलभद्र के रथ 'तलध्वज' को खींचना शुरू किया। देवी सुभद्रा के रथ 'देवदलन' जबकि भगवान जगन्नाथ के रथ 'नंदीघोष' की 'बहुड़ा यात्रा' भी शुरू हुई।

दैनिक जागरण
प्रत्येक व्यक्ति प्रशंसा चाहता है

हानिकारक खाद्य पदार्थ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों और कालेजों को यह सही निर्देश दिया कि वे अपने यहां हानिकारक खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकें और उनके स्थान पर पौष्टिक एवं स्वास्थ्यवर्द्धक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराएं, लेकिन इस निर्देश मात्र से स्थिति में शायद ही कोई परिवर्तन हो। इसका अंदेशा इसलिए है, क्योंकि यूजीसी की ओर से ऐसी पहल पहले भी की जा चुकी है। संभवतः पहले दिए गए निर्देशों की अनदेखी के कारण ही उसे फिर से निर्देश देने की आवश्यकता पड़ रही है। जो भी हो, आवश्यक केवल यह नहीं है कि शिक्षण संस्थानों में हानिकारक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता को नियंत्रित किया जाए। इसी के साथ यह भी जरूरी है कि सेहत के लिए हानिकारक माने जाने वाले खाद्य एवं पेय पदार्थों का प्रचलन यथासंभव सीमित किया जाए, क्योंकि बच्चों और युवाओं में ऐसे खाद्य पदार्थ लोकप्रिय होते जा रहे हैं, जो उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं। बिभिन्न संस्थानों में बार-बार यह सामने आ रहा है कि जंक फूड कहे जाने वाले खाद्य पदार्थ युवा पीढ़ी के स्वास्थ्य को चौपट करने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनके चलन को कम करने के लिए जैसे उपाय किए जाने चाहिए, वैसे नहीं हो रहे हैं। इससे भी खराब बात यह है कि आवश्यक नियम-कानूनों के अभाव में सेहत के लिए हानिकारक डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों की बिक्री बढ़ती चली जा रही है।

प्रोसेस्ड फूड यानी प्रसंस्कृत खाद्य सामग्री का उपयोग तो तब भी स्वीकार्य है, लेकिन अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का नियमित उपभोग तो एक तरह से बीमारियों को निमंत्रण है। समस्या यह है कि उनका भी चलन तेजी से बढ़ रहा है और कई बार यह देखने में भी आ रहा है कि ऐसे खाद्य पदार्थ बनाने वाले तय मानकों की उपेक्षा ही करते हैं। अपने देश में खाद्य पदार्थों के संदर्भ में जो नियम-कानून हैं, उनकी अनदेखी ही अधिक होती है। इसी का दुष्परिणाम है कि देश में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर भी अंकुश नहीं लग पा रहा है। ऐसा नियामक और निगरानी संस्थाओं की सुस्ती एवं लापरवाही के चलते हो रहा है। एक चिंताजनक बात यह भी है कि हानिकारक घोषित सामग्री का सरोगेट विज्ञापनों के जरिए खुलकर प्रचार किया जा रहा है। अब तो ऐसे विज्ञापन अनेक जानी-मानी हस्तियां भी कर रही हैं। इसके बावजूद ऐसा लगता है कि किसी को कोई परवाह ही नहीं है कि कहां क्या गलत हो रहा है? निश्चित रूप से सेहत की चिंता करना केवल सरकारों और उनकी एजेंसियों की ही जिम्मेदारी नहीं। इसके प्रति कहीं न कहीं आम जनता को भी जागरूक होना होगा। इस सबके बावजूद इतना तो है ही कि जिन सरकारी संस्थाओं को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है, वे अपना काम सही से करें। ऐसी संस्थाएं दावा चाहे जो करें, सच यह है कि वे अपना काम सही तरह नहीं कर रही हैं।

भ्रष्टाचार और आम आदमी

बिहार में एक तरफ शासन भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस की नीति पर काम कर रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष लगातार भ्रष्टाचार पर हमलावर है। चाहे पुल-पुलिया गिरी हो या तटबंधों की मरम्मत में गड़बड़ी हुई हो, भ्रष्टाचार का आरोप लगता ही रहा है। गंभीर बात यह कि अब मंत्री भी मानने लगे हैं कि निचले स्तर तक भ्रष्टाचारी सक्रिय हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डा. दिलीप कुमार जायसवाल का रविवार को आया बयान आम आदमी के जख्म पर थोड़ा मरहम तो लगाता है, लेकिन समस्या का निराकरण नहीं करता। मंत्री सिर्फ अपने हिस्से की बात कर रहे थे। भू माफिया की गिरफ्त में व्यवस्था का सच बता रहे थे। यदि इतना कुछ पता है तो इस तंत्र को नेस्तनाबूत करने में हिचक कैसी? सिर्फ कहने से या सिर पीटने से बात नहीं बनेगी। पूरे तंत्र को खंगालने और उसपर कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। आम आदमी चाहे जमीन का मामला हो, योजनाओं के लाभ का मामला हो, ऋण का मामला हो, अनुभव करना चाहता है कि वह वास्तविक लाभुक है। यदि कुछ योजनाओं का लाभ सीधे उसके खाते से लिंक न होता तो कल्पना की जा सकती है कि भ्रष्टाचार की व्यापकता किस स्तर पर होती। यदि विपक्ष की आलोचनाओं को गंभीरता से लिया जाए तो कई स्तरों पर गड़बड़ी के ढीले पेच को सख्त जा सकता है। आम आदमी अपने जीवन को सरल बनाने की छटपटाहट में इन्हीं व्यवस्थाओं के बीच से होकर गुजरता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि यदि शीर्ष पर बैठे लोगों की दृष्टि इस ओर गई है तो आम आदमी को राहत मिलेगी। काम कराने के लिए जगह-जगह जेब ढीली नहीं करनी पड़ेगी। सुशासन को धकियाते ऐसे भ्रष्ट तंत्र पर लगातार चोट करने की जरूरत है।

> सिर्फ कहने से या सिर पीटने से बात नहीं बनेगी। पूरे तंत्र को खंगालने और उसपर कड़ी कार्रवाई की जरूरत है

दोराहे पर खड़ा अमेरिका

शिवकांत शर्मा

अमेरिका के सामने सवाल यह है कि क्या नेता और उनके समर्थक ट्रंप पर हमले की घटना से सबक लेकर एक-दूसरे का दानवीकरण करने से बाज आएंगे?

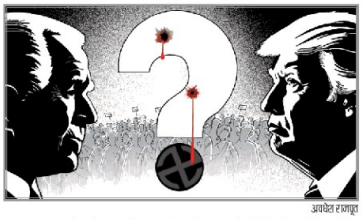

अवधेश राजपूत

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले ने अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया को राजनीति में फैल रहे बैरभाव पर सोचने को विवश किया है। गोली निशाने पर लग जाती तो कहुता के इस माहौल में क्या हो सकता था, इसकी कल्पना करना भी भयावह है। इसीलिए राष्ट्रपति जो बाइडन ने हमले की कड़ी निंदा की और लोगों से हिंसक बयानबाजी रोकने की अपील की। ट्रंप ने भी हमले के बाद कहा कि वह अपने रिपब्लिकन पार्टी के महाधिवेशन के भाषण में देश से एकजुट होने की अपील करेंगे। दोनों पार्टियों के प्रमुख नेता, राजनीतिक पंडित और मीडिया सभी इस समय समझदारी की बातें कर रहे हैं और लोगों को याद दिला रहे हैं कि लोकतंत्र और हिंसा साथ-साथ नहीं रह सकते। दोनों एक-दूसरे का विरोध हैं। ट्रंप पर हमले की दुनिया भर के नेताओं ने एक स्वर में निंदा की है। भारत में भी प्रधानमंत्री मोदी और प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हमले की कड़ी निंदा की है, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका और भारत, दोनों ही लोकतंत्रों की राजनीति में हिंसा की जड़ें बहुत गहरी और पुरानी हैं।

अमेरिका में जब-जब समाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर आपसी विरोध बढ़ा, तब-तब राजनीतिक हत्याएं और दंगे-फसाद हुए हैं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में देश जब दासता उन्मूलन के मुद्दे पर उत्तर और दक्षिण में बंट गया था, तब दासता उन्मूलन के पक्षधर राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या हुई। पिछली सदी के सातवें दशक में जब नागरिक अधिकार आंदोलन को लेकर आपसी मतभेद बढ़े, तब राष्ट्रपति जान कैनेडी, मार्टिन लूथर किंग की हत्याएं हुईं। पिछली सदी के आठवें दशक में वियतनाम युद्ध को लेकर फैली वैचारिक कटुता के बीच दो बार राष्ट्रपति जेरल्ड फोर्ड पर जानलेवा हमले हुए और 1981 में आर्थिक संकट को लेकर फैली कड़वाहट के बीच राष्ट्रपति रीगन पर हमला हुआ। विडंबना यह है कि दुनिया में सबसे अच्छी आर्थिक और सामरिक स्थिति के बावजूद अमेरिका इस समय सबसे गंभीर वैचारिक और राजनीतिक संकट के दौर में है। उसकी अर्थव्यवस्था कोविड की मार के बाद से सबसे शक्तिशाली होकर उभरी है। बेरोजगारी न्यूनतम बिंदु पर है। महंगाई काबू में आ रही है। ब्याज दरें घटने वाली हैं। चीन की कोशिश के बावजूद डालर और अमेरिकी कंपनियों का वर्चस्व कायम है, फिर भी आधी अमेरिकी जनता को पटरी पड़ा दी गई है कि उनका देश तीसरी दुनिया का देश बन चुका है। रिपब्लिकन पार्टी के ट्रंप समर्थकों की लगता है कि बाइडन सरकार देश के दरवाजे अपराधी और पागल आप्रवासियों की भीड़ के लिए खोलकर उनकी संस्कृति और मूल्य नष्ट करने पर तुली है। डेमोक्रेटिक पार्टी को वे उस डीप स्टेट या नौकरशाही तंत्र का हिस्सा मानते हैं, जो जलवायु परिवर्तन रोकने के नाम पर टैक्स बढ़ाकर देश को बर्बाद करना चाहता है। दूसरी ओर बाइडन की डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थकों को लगता है कि ट्रंप की जीत लोकतंत्र को खत्म कर तानाशाही ला देगी और ट्रंप के चुने जाते ही अमेरिका में कयामत आ जाएगी। ट्रंप अपने विरोधियों को कीड़े-मकोड़े कहते हैं, जबकि बाइडन ट्रंप को फासी, तानाशाह और अपराधी कहते हैं। लोकतंत्र में विरोधी बयानबाजी कोई नई बात नहीं है, पर अमेरिका की समस्या यह है कि वहां गनसंख्या जनसंख्या से भी अधिक है। एक आम वयस्क नागरिक आत्मरक्षा के लिए सुपर बाजार से गन खरीद सकता है। अमेरिका में मानसिक बीमारों की संख्या भी बढ़ रही है। ऐसे सामाजिक परिवेश में इंटरनेट मीडिया पर विरोधियों का दानवीकरण कच्चे मानसिक संतुलन वाले लोगों को राजनीतिक हिंसा के लिए प्रेरित कर सकता है और कर रहा है। ट्रंप पर हमला करने वाला टामस मैथ्यू क्रुक्स इसी की मिसाल है।

अमेरिका के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राजनेता और उनके समर्थक इस घटना से सबक लेकर दूसरे का दानवीकरण करने और हिंसा उकसाने वाली बयानबाजी से बाज आने को तैयार हैं? ट्रंप और उनके समर्थक अभी तो देश जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें चुनाव प्रचार में चरितार्थ कर पाएंगे? चुनाव प्रचार की दिशा इस समय ट्रंप के हाथों में है। बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा कि रिपब्लिकन पार्टी अधिवेशन में अपनी उम्मीदवारी स्वीकार करते हुए ट्रंप किस अंदाज में क्या कहेंगे? हिंसा उकसाने के मामले में सबसे अधिक अंगुलियां उन्हीं पर उठती रही हैं। ऐसी कुछ घटनाओं को बाइडन ने गिनाया भी, जैसे लोगों को अमेरिकी संसद पर धावा बोलने और अमेरिकी कांग्रेस की पूर्व सभापति नैन्सी पेलोसी के घर में घुस कर उनके पति पर हमले के लिए या फिर मिशिगन की गवर्नर के अपहरण के लिए उकसाना। हमले के कारण इस समय ट्रंप की लोकप्रियता उछाल पर है, परंतु हमले के बाद रीगन की लोकप्रियता में आए उछाल की तरह वह कुछ हफ्तों में नीचे आ सकती है। उस सूरत में ट्रंप और उनके समर्थक कितना संयम बरतेंगे? दूसरी तरफ बाइडन और उनके समर्थक लोकप्रियता में ट्रंप से पिछड़ने के कारण भारी दबाव हैं। ऐसे में क्या वे नफरती बयानबाजी से वोट पाने के लोभ का संवरण कर पाएंगे? अभी तो अमेरिकी मीडिया में संयम भरे संपादकीय छप रहे हैं, पर क्या यह संयम चुनाव प्रचार की गर्मी झेल पाएगा?

अमेरिका को इस समय इस तरह के कई प्रश्नों के उत्तर खोजने हैं। वहीं यूरोपीय देशों, चीन और भारत को एक बार फिर ट्रंप की अप्रत्याशित नीतियों के लिए कमर कसनी है, क्योंकि हमले के बाद उनके जीतने की संभावना प्रबल हो गई है। भारत समेत हर लोकतांत्रिक देश को अपने यहां राजनीति में बढ़ते बैरभाव और हिंसा तथा इंटरनेट मीडिया के जरिये फैलती उसकी गूंज के प्रभावों से निपटने के बारे में गंभीरता से सोचना होगा। शिकागो यूनिवर्सिटी की एक शोध संस्था शिकागो प्रोजेक्ट के हाल के सर्वेक्षण से पता चला है कि अमेरिका के दस प्रतिशत लोगों ने ट्रंप को सत्ता में आने से रोकने और सत्ता प्रतिष्ठान ने उन्हें सत्ता में लाने के लिए बलप्रयोग को सही ठहराया। लोकतंत्र में मनचाही सत्ता के लिए वोट की जगह लाठी के प्रति बढ़ता लोगों का यह विश्वास खुद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रहरी मानने वाले अमेरिका के लिए ही नहीं, हर लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है।

(लेखक बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं)

response@jagran.com

सवालों से घिरी हुई प्रशासनिक सेवा

प्रेमपाल शर्मा

देश को प्रशासनिक व्यवस्था देने वाले स्टील फ्रेम में इन दिनों बहुत तेजी से गिरावट नजर आ रही है

पूजा खेडकर के घर नोटिस चिपकाता पुलिसकर्मी। प्रेट्र

प्रशिक्षु आइएएस अधिकारी पूजा खेडकर प्रकरण ने देश की प्रशासनिक सेवा की कई संस्थाओं के कारनामों की एक साथ उजागर कर दिया है। पूजा खेडकर अभी लालबहादुर शास्त्री अकादमी, मसूरी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। उनकी यह ट्रेनिंग अगले साल जुलाई में पूरी होगी। इस दौरान उन्हें पुंछ ट्रेनिंग के लिए असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में पुणे भेजा गया। वहां जाते ही उन्होंने सभी नियम-कायदे और नैतिकता को ताक पर रख ऐसे-ऐसे काम किए, जो देश की पूरी प्रशासनिक सेवा के लिए कलंक कहे जा सकते हैं। उन्होंने वहां जाते ही लाल बत्ती लगी सरकारी गाड़ी, एक अलग आफिस, घर और चपरासी इत्यादि की मांग की। यहां तक कि अपनी निजी आडी गाड़ी पर खुद ही अवैध रूप से लाल बत्ती भी लगवा ली, जबकि उस गाड़ी के खिलाफ यातायात नियमों के उल्लंघन के दर्जन भर मामले दर्ज हैं और जुर्माना तक बकाया है। बीते दिनों उसे जब्त कर लिया गया। आइएएस अधिकारी बनने के बाद उन पर ऐसा नशा छाया कि पुणे में तैनात एक अन्य अफसर के कार्यालय से जबरन उनका नाम हटाकर अपनी नेम प्लेट लगा दी।

हालांकि इस प्रकरण के सामने आना एक मायने में सही साबित हुआ है। इस प्रकरण से न जाने कितने ज्वलंत प्रश्न खुलकर सामने आ गए हैं। पहला सवाल तो यही है कि पूजा खेडकर को ओबीसी सर्टिफिकेट कैसे मिल गया? जब उनकी खुद की संपत्ति 17 करोड़ रुपये दर्ज है। उनके पिता भी एक पूर्व अधिकारी होने के साथ-साथ राजनीति में कदम बढ़ा रहे हैं। उन्होंने हाल में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में अपनी संपत्ति 40 करोड़ रुपये और आय 43 लाख रुपये वार्षिक दिखाई है। यह ठीक है कि पूजा खेडकर ओबीसी समुदाय से आती हैं, लेकिन आठ लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले तो क्रीमीलयर के दायरे में आते हैं। ऐसे लोग आरक्षण के हकदार नहीं होते। इससे स्पष्ट होता है कि उन्हें ओबीसी प्रमाण पत्र गलत तरीके से दिया गया। इसके अलावा उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा ओबीसी कोटे के साथ-साथ दिव्यांग उम्मीदवार के रूप में दी। ऐसे किसी सर्टिफिकेट के मामले में सत्यापन के लिए विशेष मेडिकल परीक्षा होती है, परंतु यूपीएससी द्वारा कई बार बुलाने पर भी वह इसके लिए नहीं गईं। हर बार एक नया बहाना बनाती रहीं, फिर उन्होंने खुद को दिव्यांग साबित करने के लिए एक निजी क्लीनिक से प्रमाण पत्र बनवाकर पेश कर दिया। यह मामला यूपीएससी की तरफ से कोर्ट में भी गया, लेकिन इसके बावजूद निजी क्लीनिक वाला उनका प्रमाण पत्र मान्य हो गया। आखिर यह कैसे स्वीकार हो गया? यह किसके दबाव में किया गया? ओबीसी और दिव्यांगता के वर्ग में उनकी रैंक 841 थी। यानी उनसे ऊपर अन्य मेधावी और सक्षम उम्मीदवार थे, जिनकी कीमत पर उन्हें जगह मिली। इस प्रकार यह ओबीसी वर्ग के दूसरे छात्रों और दिव्यांगों की हकमारी का मामला भी है। निश्चित रूप से यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए ओबीसी के पैमाने से लेकर उन सभी मानकों की भी अनदेखी है, जिनका उल्लंघन करते हुए वह आइएएस बन गईं। ऐसे लीग मेरिट की कीमत पर लगातार जगह बना रहे हैं।

इस प्रकरण में एक बात साफ नजर आ रही है कि बिना राजनीतिक और प्रशासनिक सांठगांठ के पूजा खेडकर यहां तक नहीं पहुंच सकती थीं। आइएएस बनने के लोभ में वह वहां से पहले भटक गईं और उन सुविधाओं की मांग करने लगीं, जो प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए ज्यादातर अफसर करते हैं। आखिर उनके जैसे अधिकारी जनता की सेवा कैसे करेंगे? वह ऐसी अकेली अधिकारी नहीं हैं। उनसे पहले इस सूची में कई नाम दर्ज हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के तमाम मामले दर्ज हैं। चाहे अभी जेल में बंद आइएएस पूजा सिंघल हों या मध्य प्रदेश के आइएएस दंपती। दरअसल नौकरशाही का कोई विभाग इससे अछूता नहीं है। अगर हाल का उदाहरण लें तो तीन वर्ष पहले जिस आइपीएस अधिकारी ने यूपीएससी की पृथिव्स यानी नैतिकता के प्रश्नपत्र में सबसे ज्यादा नंबर पाए थे, उसके अगले वर्ष की परीक्षा में उसे नकल करते पकड़ा गया। इससे जाहिर होता है कि भारत जैसे विशाल देश को एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था देने वाले इस स्टील फ्रेम में बहुत तेजी से गिरावट आ रही है।

हमारी सभ्यता सदियों पुरानी है। इसकी समृद्धि का गुणगान इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इसके बावजूद समाज के विभाजन ने इसे इतना जर्जर कर दिया कि हम हजारों साल तक कभी मुगलों तो कभी अंग्रेजों के गुलाम बने रहे। दुख की बात है कि जाति, पंथ और क्षेत्र के नाम पर लगभग वैसा ही विभाजन आज हमारी प्रशासनिक सेवाओं में प्रवेश कर चुका है। राजनीति और नौकरशाही का गठजोड़ इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। इससे छुटकारा पाने के लिए देश की नौकरशाही के मौजूदा रूप यानी उसकी भर्ती से लेकर ट्रेनिंग और सुविधाओं में तुरंत सुधार करना होगा। नौकरी की सुरक्षा और सुविधाएं ही बार-बार पूजा खेडकर जैसे अधिकारियों को जन्म देती हैं। यदि देश को कोई सही संदेश देना है तो पूजा खेडकर के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रशिक्षण अवधि के दौरान बरखास्त करने में कोई सेवा नियम आड़े नहीं आता। इसके साथ ही सरकार ने पूजा खेडकर पर लगे आरोपों की जांच के लिए जो समिति बनाई है, उसका वह दायित्व भी बनता है कि उनके मेडिकल सर्टिफिकेट से लेकर ओबीसी सर्टिफिकेट देने के मामलों की जांच करे, क्योंकि यह प्रकरण यूपीएससी और कार्मिक मंत्रालय के साथ-साथ देश की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था की साख का भी है।

(लेखक भारत सरकार में संयुक्त सचिव रहे हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

खुशी को पहचानें

आज आवेश, उत्तेजना एवं चंचलता से जीवन की धारा बदल गई है, इसलिए मन में अशांति बढ़ रही है। हमने खुद को कई गैरजरूरी चीजों से घेर रखा है, जो गाहे-बगाहे हमें घटकाती ही हैं। हम तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं एवं तत्काल खुशी चाहते हैं। इसके लिए शार्टकट अपनाते हैं। वास्तव में जो चाहते हैं, उसे पाना सफलता है। जो मिला है, उसे चाहना खुशी है।

व्यक्ति में शक्तियों का अकूत भंडार है। शक्तियों को जगाकर इनका उपयोग कर व्यक्ति अनेक परिस्थितियों को सह सकता है। भविष्य की चिंता में खोने वाला व्यक्ति वर्तमान के सुख को भूलता जा रहा है। कल्पनाओं का हवाई महल निर्मित कर दुख का जाल बुनता जा रहा है। आकस्मकता इस बात की है कि व्यक्ति सपने देखे तो उसमें रंग भी भरे। विशिष्टता का बीज हमारे अंदर है अर्थात शक्ति का स्रोत हम खुद हैं। हम अपनी शक्ति का उपयोग तभी कर सकेंगे जब उसे पहचानेंगे। केवल हवाई बातें करने से कुछ हाथ नहीं आता। योजना की गाड़ी पर सवार होकर ही लक्ष्यों तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन इसके लिए योजना पर भरोसा रख उस पर काम भी करना होगा। सफलता का कोई और रास्ता ही नहीं है। जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है-यही विश्वास मनुष्य के सफल जीवन का सूत्र है। इसके लिए धैर्य, संकल्प और आत्मविश्वास जरूरी हैं।

नए लक्ष्य की चाह रखने वालों को रास्ते भी नए तय करने पड़ते हैं। हर रोज एक ही रास्ते पर चलने से, देखे हुए नजारे ही दिखते हैं। हमारी समस्या यह है कि हम नजारे नए देखना चाहते हैं, पर पुराने रास्तों को छोड़ने का जोखिम नहीं उठाना चाहते। अगर कुछ ऐसा पाना चाहते हैं, जो पहले से नहीं है, तो उसके लिए करना भी कुछ ऐसा ही होगा, जो पहले कभी नहीं किया। जब व्यक्ति के भीतर कुछ करने की चाह जागृत हो जाती है तो वह असंभव कार्य भी संभव हो जाता है।

ललित गर्ग

कामकाजी महिलाओं की सेहत का ध्यान

सुनीता मिश्रा

> वर्तमान में घर को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए महिलाएं कुशल एवं अकुशल श्रमिक के रूप में हर क्षेत्र में कार्य कर रही हैं

हाल में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को राज्यों और अन्य पक्षों के साथ परामर्श कर महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश पर एक माडल नीति तैयार करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि यह मुद्दा नीति से संबंधित है और अदालतों के विचार करने के लिए नहीं है। महिलाओं को ऐसी छुट्टी देने के संबंध में अदालत का निर्णय प्रतिकूल और हानिकारक साबित हो सकता है, क्योंकि नियोक्ता उन्हें काम पर रखने से परहेज कर सकते हैं।

बर्तमान में घर को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए महिलाएं कुशल एवं अकुशल श्रमिक के रूप में हर क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। साथ ही अपने परिवार की सभी जिम्मेदारियां भी बखूबी निभा रही हैं। इस दौरान उन्हें मासिक धर्म में असहनीय पीड़ा के बावजूद काम करने पर मजबूर होना पड़ता है। मासिक चक्र एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इस दौरान महिलाओं को कई तरह की शारीरिक और मानसिक कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। घर के साथ वे कार्यालय में सामान्य दिनों की भांति कार्य कर पाने में अक्षम होती हैं। कई बार तो वे काम के दबाव में और अपनी जिम्मेदारियों का निवर्हन करते हुए इस दर्द को बर्दाश्त करती रहती हैं।

माहवारी के दौरान महिला कर्मियों को अवकाश मिले इस पर लंबे समय से बहस जारी है। इसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि माहवारी में छुट्टी की मांग करने वाला भारत अकेला देश नहीं है। स्पेन, आस्ट्रेलिया, जापान, वियतनाम, फिलीपींस, चीन, दक्षिण कोरिया, ताइवान, जांबिया, इंडोनेशिया और इटली में पहले से ही इन दिशों में पेड लीव का नियम है। वहीं भारत में सिर्फ तीन राज्यों बिहार, केरल और सिक्किम में मासिक धर्म के दौरान छुट्टी को लेकर नियम हैं। बिहार पहला ऐसा राज्य है, जो 1992 से राज्य की महिला कर्मचारियों को मासिक धर्म में दो दिन का विशेष अवकाश दे रहा है।

पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करने वाली महिलाएं काफी मेहनती होती हैं। इनमें से कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं, जो प्रतिदिन बस और ट्रेन में घंटों सफर तय कर दूसरे शहरों में काम करने के लिए जाती हैं। इसका एक बड़ा कारण निजी हास्टलों का महंगे होन है, जिसके चलते कामकाजी महिलाएं इन हास्टलों में खर्च करने की बजाय प्रतिदिन घंटों का सफर तय करने को मजबूर होती हैं। माहवारी के समय घंटों का सफर तय करना असहनीय हो जाता है। दूसरी ओर स्वच्छ शौचालय की सुविधा मुहैया नहीं होने के कारण कार्यस्थल पर महिलाओं का स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है, जिसके बारे में वे किसी से कुछ कह भी नहीं पाती हैं। कई बार नौकरी तक छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऐसे में अगर भारत में यह नियम लागू होता है, तो हर क्षेत्र में नौकरी करने वाली महिलाओं की संख्या में इजाफा होगा।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

बेमेल कुनबे की दरकती एकता

'आइएनडीआइए के जटिल समीकरण' शीर्षक से युक्त आलेख में राज कुमार सिंह ने कांग्रेस नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन आइएनडीआइए की एकजुटता पर जो सवाल खड़े किए हैं, उनकी बानगी चार राज्यों के आसन्न विधानसभा चुनावों की तैयारी के मद्देनजर दिखने लगी है। वस्तुतः प्रधानमंत्री मोदी के विरुद्ध एकजुट होने वाले विपक्षी दलों ने जो गठबंधन बनाया था, उसका एकमात्र उद्देश्य लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों को हराकर मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकना था। विभिन्न राज्यों में आइएनडीआइए के सहयोगी दलों के साथ चुनावी गठबंधन करके, आरक्षण और संविधान को खत्म करने जैसे झूठे नैरेटिव गढ़ कर कांग्रेस ने अपनी सीटें जरूर बढ़ा लीं, लेकिन मोदी को तीसरी बार फिर से सत्तासीन होने से नहीं रोक पाई। 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी विरोध को लेकर परवान चढ़ी विपक्षी एकजुटता निकट भविष्य में होने वाले विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी वैसी ही बनी रहेगी, इसमें संदेह है। उप्र में सपा और दिल्ली में आप कांग्रेस को लेकर सशंकित हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक भी सीट नहीं जीत पाई। वहीं उप्र में सपा के प्रभाव का कांग्रेस ने तो फायदा उठा लिया, लेकिन सपा उम्मीदवारों को कांग्रेस के साथ गठबंधन का विशेष लाभ नहीं मिल पाया। ऐसे में अपने नफा-नुकसान को नजरअंदाज कर आइएनडीआइए में सम्मिलित विभिन्न सहयोगी दल पहले की तरह एकजुट रह पाएंगे, इसकी उम्मीद नहीं दिखती। लोकसभा के अंदर उठने वाले विभिन्न मुद्दों पर भी अपनी अलग-अलग वैचारिक पृष्ठभूमि और राजनीतिक हितों को लेकर विपक्षी गठबंधन की एकता के दरकने की संभावना बनी रहेगी। ऐसे में यदि आइएनडीआइए नाम के इस बेमेल कुनबे की दरकती एकता का लाभ सत्ता पक्ष में बैठी भाजपा उठा ले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।

pandeyvp1960@gmail.com

मर्यादा का पालन जरूरी

हृदयनारायण दीक्षित का आलेख 'संसद की गरिमा पर संकट' अत्यंत सटीक है। संसद गंभीर विषयों पर गहन विचार का मंच है। रचनात्मक सुझाव देने का मंच है। राजनीतिक मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से तो संसद में मनभेद, यहां तक कि नफरत की राजनीति अधिक दिख रही है। पूरे के पूरे सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाते हैं। उदाहरण के लिए पेगसस मुद्दे, हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर पूरे सत्र में हंगामा हुआ। स्वतंत्र जांच और बाद की रिपोर्ट के बाद इनमें लेशमात्र भी सच्चाई नहीं मिली। अठारहवीं लोकसभा के पहले सत्र में तो मर्यादा, शिष्टाचार तार तार हो गए। विपक्ष ने मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई तक देने की औपचारिकता नहीं निभाई। उनके शपथ ग्रहण तक का बायकाट किया। प्रधानमंत्री तथा मंत्रियों के शपथ लेते वक्त भी हूटिंग की गई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने पहले भाषण में हिंदुओं को हिंसक तक बता दिया। प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत टिप्पणियां की। अग्नीवीरों को लेकर तो सरासर झूठ बोला कि उनके बलिदान होने पर उन्हें कोई क्षतिपूर्ति राशि नहीं मिलती। जब मोदी ने अपना भाषण दिया तब कांग्रेस और कुछ विपक्षी सदस्यों ने पूरे समय जबरदस्त शोर मचाया। जहां नेता प्रतिपक्ष इतना गैर जिम्मेदार हो और अपने पद की मर्यादा के अनुसार आचरण न करे तो संसदीय अनुशासन और शिष्टाचार में गिरावट निश्चित है। समय-समय पर संसद और विधानसभा में अनुशासन और शिष्टाचार बनाए रखने के लिए अनेक सम्मेलन हुए हैं। बहुत से प्रस्ताव भी पास हुए हैं, लेकिन व्यावहारिक तौर पर अनुशासन, शिष्टाचार और मर्यादा का स्तर लगातार गिर रहा है। संसद की कार्यवाही टीवी चैनलों पर दिखाई जाती है। वहां का हंगामा पूरा देश देखता है, संवेदनशील लोगों को पीड़ा भी बहुत पहुंचती है, लेकिन संसद सदस्यों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकतंत्र और संविधान बचाने का दम भरने वाले संसद की गरिमा तक का ध्यान नहीं रख रहे हैं। यह अत्यंत दुखद है।

सीपी बंसल, दिल्ली

उस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। मंगलवार, 16 जुलाई 2024

बिलों पर बढ़ेगी मेहनत

बीते सप्ताह राज्यसभा के चार मनोनीत सदस्यों के अपना कार्यकाल पूरा कर लेने के बाद सदन में BJP सदस्यों की संख्या घटकर 86 रह गई। सदस्यता हासिल करने के बाद ये चारों औपचारिक तौर पर BJP से जुड़ गए थे। जाहिर है, अब सत्तारूढ़ पार्टी के फ्लोर मैनेजरों को बहुमत साधने के लिए थोड़ी और मशक्कत करनी पड़ेगी।

बहुमत से दूर | वैसे, राज्यसभा में बहुमत से दूरी BJP के लिए कोई नई बात नहीं है। लोकसभा में अपने दम पर बहुमत लेकर सरकार बनाने के बाद भी बीते दस वर्षों में उसे ऊपरी सदन में बहुमत प्रायः मैनेज ही करना पड़ा। आज भी जब लोकसभा में सत्तारूढ़ NDA को पूर्ण बहुमत हासिल है, राज्यसभा में उसकी कुल सदस्य संख्या 101 तक ही पहुंच पा रही है। 225 की मौजूदा सदस्य संख्या वाले सदन में साधारण बहुमत के लिए 113 का आंकड़ा जरूरी है।

बहुमत से दूर NDA

अन्य दलों पर निर्भरता | ऐसे में जब इसी महीने की 22 तारीख से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है, केंद्र सरकार की NDA से बाहर के दलों पर निर्भरता बढ़ गई है। हालांकि अब तक के अनुभव की रोशनी में देखें तो इन दलों के बीच से जरूरी समर्थन जुटाना सरकार के लिए कोई मुश्किल लक्ष्य नहीं है। खासकर तब, जब 11 सदस्यों वाली YSR कांग्रेस और 4 सदस्यों वाली AIADMK जैसी पार्टियां समर्थन देने को तैयार नजर आती हों।

बहुमत से दूरी घटेगी | वैसे, राज्यसभा में सत्तारूढ़ गठबंधन की बहुमत से यह दूरी बनी नहीं रहने वाली। अभी सदन की कुल 20 सीटें खाली हैं। इनमें 11 सीटें निर्वाचित प्रतिनिधियों की हैं, जिनके लिए चुनाव इसी साल होने हैं। विधायकों की मौजूदा संख्या को देखते हुए इनमें से सात सीटें सहयोगी दलों को मिलनी तय मानी जा सकती हैं। इसके अलावा अगर महाराष्ट्र में विधायकों को एकजुट रखा जा सका तो दो और सीटें इनके खाते में जुड़ जाएंगी।

विपक्ष का ताप | दूसरी ओर विपक्ष को देखें तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के पास अभी 26 सदस्य हैं। तेलंगाना विधानसभा की बदली सूरत के मद्देनजर वहां से एक सीट का इजाफा होना भी लगभग तय है। चूंकि नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए न्यूनतम 25 सीटों की जरूरत होती है, इसलिए उस पर पार्टी को कोई खतरा नहीं है। कुल मिलाकर, आशा की जा सकती है कि विधेयकों पर राज्यसभा में आने वाले वक्त में सार्थक बहस दिखेगी।

आजकल

मीम्स की मूर्ति

करे कोई, भरे कोई। यों तो यह कहें कि ससुर ने किया और दामाद को भरना पड़ा। पिछले साल अक्टूबर के आखिरी दिनों में दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस के सह-संस्थापक नारायण मूर्ति ने कहा था कि देश के युवाओं को सप्ताह में 70 घंटे काम करना चाहिए। मूर्ति ने यह बात इंफोसिस, किसी अन्य कंपनी या सरकारी कर्मचारियों को लेकर नहीं कही थी। वह सिर्फ यह कह रहे थे कि भारत को प्रॉडक्टिविटी बढ़ानी चाहिए और इसके लिए युवाओं को सप्ताह में 70 घंटे काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब मूर्ति ने यह बात कही थी, तब सोशल मीडिया पर मीम्स बने थे। उनकी बात पर मीडिया में बहस हुई थी। और हाल ही में जब उनके दामाद और टोरी लीडर ऋषि सुनक को ब्रिटेन के संसदीय चुनाव में लेबर पार्टी के हाथों करारी हार मिली तो मूर्ति के 70 घंटे वाले बयान का जिन्न फिर से मीम के रूप में बोतल से बाहर आ गया। सोशल मीडिया पर इस तरह के तंज कसे जाने लगे कि मूर्ति की बात पर अगर सुनक ने अमल किया होता तो चुनाव में उनकी पार्टी का इतना बुरा हश्र नहीं होता। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि अब जबकि सुनक के हाथों से ब्रिटेन के पीएम की कुर्सी निकल गई है तो क्या वह भारत लौटकर अपने ससुर की 70 घंटे काम वाली बात पर अमल करेंगे? जब मूर्ति ने 70 घंटे काम वाला बयान दिया था, तब यह तर्क भी दिया गया कि कोई फेरी वाला या छोटा दुकानदार, जो अपना धंधा करता है, वह पहले से ही सप्ताह में 70 से अधिक घंटे काम कर रहा है, फिर इस बयान पर इतना हो-हल्ला नहीं मचना चाहिए। लेकिन यहां एक पेच है। जो शख्स अपना काम कर रहा है, उससे होने वाला सारा मुनाफा उसी की जेब में जा रहा है। वहीं, किसी कंपनी के एंप्लॉयी के अधिक घंटे तक काम करने से जो प्रॉडक्टिविटी बढ़ेगी, उसका फायदा उस फर्म को होगा। हां, यह जरूर हो सकता है कि कंपनी उस कर्मचारी के काम से खुश होकर साल के आखिर में उसका वेतन बढ़ा दे या उसे बोनस दे दे। ऋषि सुनक की हार पर मूर्ति के 70 घंटे वाले बयान पर ताने इसलिए भी आए क्योंकि वर्क-लाइफ बैलेंस पर आज कहीं ज्यादा जोर है। 1922 में हेनरी फोर्ड ने जब फोर्ड मोटर्स में सप्ताह में 40 घंटे काम का रूल बनाया, तब उनके दिमाग में शायद यही बात रही होगी। इसके बाद दुनिया में कई जगहों पर सप्ताह में 40 घंटे काम एक तरह से नियम ही बन गया। अब तो विकसित देशों में इसे घटाकर 30-32 घंटे तक लाने की मांगें हो रही हैं।

बोल वचन

बासी भात, तेवासी माठा

राहुल पाण्डेय

बहुत कम ही लोग होंगे, जिन्होंने जीवन में बासी भात या बासी रोटी ना खाई हो। बासी, यानी कल का बचा खाना। बासी तो खाते ही हैं, बहुत लोग तेवासी भी खाते हैं। तेवासी, यानी बीत चुके कल के भी एक दिन पहले का। अवध के ब्रह्मभोज में बनने वाली पूरियों का कद रोटी से भी थोड़ा निकलता हुआ होता है, इसलिए इसे यहां सोहारी कहते हैं। बासी सोहारी लोग बासी सब्जी के साथ खाते हैं। तेवासी होते-होते सोहारी थोड़ा सूख जाती है। ऐसे में उसका बूरा बनाकर दूध, दही या मट्ठे के साथ खाते हैं। मट्ठा तो वैसे भी तेवासी ही ज्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि तब उसमें हलकी सी खटास और महक बढ़ जाती है। तेवासी मट्ठे के लिए अवध में लोकोक्तियां भी हैं। एक तो यही- 'बासी भात, तेवासी माठा, औ ककरी के बतिया, आधी रात जुड़ावनि आवै, भूंई लेहौ या खटिया।' यानी ये सब खाकर जी एकदम शीतल हो जाता है। शायद इसीलिए ओडिशा वाले अपने पाखाल को तेवासी करने के बाद ही खाना ज्यादा पसंद करते हैं। बासी-तेवासी का एक बड़ा हिस्सा औरतों के खाते में दर्ज है। भोजन को इतना सिरजने पर भी उन्हें इज्जत नहीं, बल्कि जिल्लत ही मिलती है। इसके लिए भी लोकोक्ति है- 'सात बासी, सात तेवासी, बजरिया कहै रात के उपासी।' यानी सात बार बासी खाया, सात बार तेवासी खाया, फिर भी बहुत कह रही है कि रात भर से कुछ नहीं खाया। बासी के लिए तो इंग्लिश में stale शब्द है, लेकिन तेवासी के लिए ऐसा कोई एक शब्द नहीं है जो परिभाषित कर सके। करेगा भी कैसे। अंग्रेज बासी तो खा लेते हैं, मगर तेवासी तो खाते नहीं।

Subrata Dhar

राजनीतिक विरोधियों के लिए हद दर्जे की नफ़रत अमेरिका की ही तरह हिंदुस्तान में भी दिखती है

ट्रंप पर हमला, भारत के लिए क्या हैं सबक

अवधेश कुमार

अमेरिका जैसे पुराने लोकतांत्रिक देश में रिपब्लिकन राष्ट्रपति उम्मीदवार डॉनल्ड ट्रंप की हत्या का प्रयास अचंभित करने वाली घटना है। ट्रंप इस हमले में बाल-बाल बचे हैं। दोनों हमलावर सुरक्षाकर्मियों की गोली का शिकार हो चुके हैं। हमले के कारणों का पता आने वाले समय में चलेगा, लेकिन इसकी सूचना आते ही पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि अमेरिकी समाज में हिंसा की कोई जगह नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें सभ्य तरीके से व्यवहार करना चाहिए। राष्ट्रपति जो बाइडन ने भी हमले की निंदा करते हुए यही बात कही। बाइडन ने ट्रंप से फोन पर बातचीत भी की।

नफरत का नैरेटिव | सच यह भी है कि डेमोक्रेटिक सहित अमेरिका के बुद्धिजीवी, मीडिया, यहां तक कि प्रशासन के एक बहुत बड़े वर्ग ने डॉनल्ड ट्रंप और उनकी विचारधारा के प्रति जिस ढंग से घृणा पैदा की है, उसका असर अमेरिकी समाज पर है। ट्रंप को हिटलर से लेकर न जाने क्या-क्या उपाधि दी गई है। उन्हें लोकतंत्र, अमेरिकी समाज और देश की एकता-अखंडता के लिए सबसे बड़ा खतरा बता दिया गया है। अमेरिका में ऐसे निहित स्वार्थी समुदाय हैं, जिनके अंदर यह भाव गहरा हुआ है कि अगर ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने तो उनके लिए समस्याएं पैदा होंगी। बड़ी संख्या में गैर-अमेरिकियों और अवैध प्रवासियों को लगता है कि उन्हें देश से जाना पड़ सकता है या फिर उन्हें यहां कैपो और जेलों में रहना पड़ सकता है।

चुनाव से बाहर करने का प्रयास | संयोग देखिए कि ट्रंप पर गोली उस समय चली जब वह एक चार्ट पढ़ते हुए बता रहे थे कि अमेरिकी सीमा पार करने वाले अवैध प्रवासियों की संख्या कितनी है। ट्रंप एवं उनके समर्थकों ने अमेरिका में अवैध रूप से आने और रहने को एक बड़ा मुद्दा बनाया है। इसे व्यापक समर्थन भी मिल रहा है। यह अनायास नहीं है कि ट्रंप को किसी तरह राष्ट्रपति की दौड़ से बाहर करने के हर प्रयास अमेरिका में हुए हैं, हो रहे हैं। सही कहिए या गलत, पर न्यायालय द्वारा सजा दिलाकर उन्हें राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से वंचित करने की कोशिशें जारी हैं।

मोदी और संघ पर निशाना | इसी संदर्भ में भारत को देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, BJP और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे हिंदुत्व विचारधारा को मानने वाले संगठनों को लेकर ऐसा ही वातावरण बनाने की कोशिश हुई है। इन संगठनों को फासिस्ट, अल्पसंख्यक विरोधी, हिंसक, भारतीय समाज की एकता का दुश्मन लोकतंत्र और खुले समाज से नफरत करने वाला कहा गया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद में ही इन लोगों को हिंसा और नफरत का प्रतीक बताया। एक बड़े वर्ग के अंदर यह भावना पैदा कर दी गई है कि अगर देश व समाज को बचाना है तो इन सबको हर स्तर पर पराजित और कमजोर करना होगा। पूरे देश के एक बड़े तबके में उनके विरुद्ध घृणा और हिंसा का भाव पैदा हुआ है। स्वाभाविक है, इसकी प्रतिक्रिया में इन संगठनों के कार्यकर्ताओं, नेताओं और समर्थकों में भी गुस्सा पैदा हुआ है।

बढ़ रहा है गुस्सा | इस समय विश्व भर में इस तरह की प्रवृत्ति चिंताजनक रूप से उभरी है। पूर्व में क्रांति कर सत्ता बदलने के विचार-व्यवहार वाले कम्युनिस्टों की जगह एक ऐसी नव वाममार्गी विचारधारा पूरी दुनिया में दिख रही है जो राष्ट्रवाद, रिलीजन, मजहब और अपने देश की सभ्यता संस्कृति पर गर्व करने वाले संगठनों को लेकर घृणा और विरोध का नैरेटिव पैदा कर रहा है। उसके परिणाम भी सामने आए हैं। भारत और अमेरिका दो देश इस समय इन मामलों में सबसे आगे हैं। इन दोनों देशों के अंदर समाज में तनाव और गुस्सा धीरे-धीरे बढ़ाया गया है।

पारिवारिक संरचना का असर | यह अजीब किस्म का नया वामपंथ है जिसकी अपनी विचारधारा स्पष्ट नहीं लेकिन ये उसी तरह की रैडिकल बातें करता है। हैरत की बात यह है कि इनमें विश्व के बड़े-बड़े पूंजीपति, कॉरपोरेट, NGO और संस्थान शामिल हैं। अमेरिका में इनकी संख्या ज्यादा है। इसलिए उनका प्रभाव वहां सर्वाधिक दिखा है। भारत में संघ, BJP और ऐसे कुछ संगठनों के जमीनी काम की बदौलत यहां उनका वैसा प्रभाव नहीं दिखता है। कई बार एक ही परिवार में दोनों विचारधाराओं के लोग दिखते हैं। इस तरह की पारिवारिक सामाजिक संरचना दूसरे देश में नहीं है। सच कहें तो इसी कारण हम बचे हुए हैं। फिर भी समय-समय पर हिंसा, तनाव और संघर्ष यहां भी दिख जाते हैं।

चुनौती बड़ी है | डॉनल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश सबके लिए सबक होना चाहिए। राजनीति और सार्वजनिक जीवन में असहमति, मतभेद और वैचारिक टकराव स्वाभाविक है। लेकिन राजनीति और सार्वजनिक जीवन में घृणा और दुश्मनी का कोई स्थान बिलकुल नहीं होना चाहिए। हालांकि जैसा माहौल भारत, अमेरिका सहित कई देशों में बन चुका है, उसमें कोई तत्काल इससे सबक लेगा इसकी संभावना कम लगती है। इसलिए सबके सामने यही प्रश्न है कि स्थिति को संभालें कैसे।

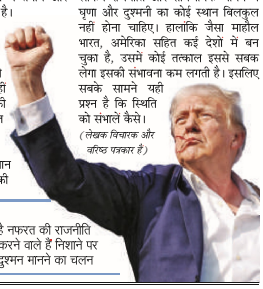

(लेखक विचारक और वरिष्ठ पत्रकार हैं)

क्या हैं चिंता के मसले

- हर जगह हावी हो रही है नफरत की राजनीति
- अपनी संस्कृति से प्रेम करने वाले हैं निशाने पर
- वैचारिक विरोधियों को दुश्मन मानने का चलन

नागिन डांस करने का है, किदर है शादी

नमिता जोशी

मुन्ना भाई आज अगर तुम अपुन का बात नहीं माना तो अपुन आज अपना मोबाइल तोड़ के समंदर में फेंकने वाला है। गलफ्रेंड भी ब्रेकअप करके भाग गयेली है, अब तो कुछ करना इच पड़ेगा। सर्किट का मॉर्निंग सिकनेस स्टार्ट हो गयेला है सुबह-सुबह। बात मोबाइल दरिया में फेंकने की आ गई तो पूछना पड़ा, क्या मैटर है सर्किट। काइकू दरिया में डाल रयेला है फोन? सर्किट बोला, मुन्ना भाई फोन पे गुस्सा इसलिए निकाल रयेला है क्योंकि पूरा दस दिन से सोशल मीडिया में शादी का फोटो- विडियो देख के अपुन का भेजा झाई हो गयेला है। अपुन कू भी सेठ की शादी में जाने का बावा। मस्त खाना खाने का है और जमीन में लेट-लेट के डांस करने का है। कुछ भी करके अपुन कू भी एंट्री मारने का है।

सर्किट का रोना सुन के छोटा छतरी बोला, ऐसे फटेले कपड़े पहन के तेरे कू भीख जरूर मिल जाएगी पन शादी में एंट्री का भूल जा। छतरी की बात का जवाब सर्किट के पास था, अपुन अभी जा रयेला है बुध बाजार से डिजाइनर ड्रेस लेने। उदर सबका कॉपी मिल रयेला है। तुमकू क्या लगता है, सब के सब डिजाइनर कपड़े पहन के आ रयेले है? आधी से ज्यादा जनता भाड़े की ड्रेस पहनती है शादी में। अपुन तो बुध बाजार से खरीद के लाएगा गोल्डन कलर का रमेश मल्होत्रा का कॉपी किया शेरवानी ड्रेस।

तभीच चम्मन चिरकुट ने राइट टाइम पे एंट्री लिया। किदर कू जा रयेला है? किसकी शादी में पहनेगा? दस दिन वाले

Ai Image

भेजा फ्राई

फंक्शन खल्लास हो गयेले। सब गेस्ट लोग भी निकल गए, सबका खाना भी हजम हो गया होगा अब तक। किसी और सेठ की शादी में जाना है तो बोल। अपुन अभी के आ रयेला है। पांच गली छोड़ के एक शादी की लाइटिंग लग रयेली है। रापचिक अरेंजमेंट है। बता क्या करने का है?

चिरकुट अक्खा लाइफ में पहली बार कुछ काम का बात किया। बोल सर्किट, क्या करेगा शादी में? अच्छे कपड़े पहन के रेड कार्पेट पे फोटो खिंचाने का है, कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पोस्ट कर के, स्टोरी डाल के दोस्तों को जलाना है, बरात में ढोल पे नागिन डांस करने का है?

सर्किट बोला, जा पहले मालूम करके आ वहां कितने दिन का प्रोग्राम बनेला है। अपुन कू सारी हसरत पूरी करने का है। ब्रेकअप का गम भुलाने का है, अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदार को जलाने का है, सोशल मीडिया में एक साथ पांच सौ फोटो डालने का है। मुन्ना भाई तो मालूम नहीं कब शादी बनाएगा पन अपुन कू बरात में फुल मूड में ढोल पे अइसा नाचने का है, जइसे अपने भाई की शादी हो रयेली हो। एक बार अंदर एंट्री मिल गई तो खाने के एक-एक स्टॉल पे अपुन अइसे टूट पड़ेगा, जइसे आसमान से बिजली।

चिरकुट सर्किट के अरमान पूरा करने के वास्ते भागा कि किस सेठ के घर में शादी है और कितने दिन का शो ऑफ करने कू मिलेगा। इधर सर्किट अजीमोश्शान शहंशाह वाला गाना लगा के शेरवानी में वॉक करने की प्रैक्टिस करने लगा। दस मिनट बाद चिरकुट आया और खोपचे में बैठ के धीरे से बोला, शादी के फंक्शन तो उदर भी पांच-छह दिन के हैं, खाने-पीने और नाचने-गाने का भी मस्त अरेंजमेंट है। मगर वो शादी जिस सेठ के घर में है वो सर्किट की गर्लफ्रेंड का पापा है। रिकी भाभी शादी कर रयेली है किसी और से। बोल सर्किट जाने का है तेरेकू उसमें शो-ऑफ के वास्ते?

मुंबइया स्टाइल में मुन्ना और सर्किट का ये भेजा फ्राई आपको कैसा लगा? हमें अपनी राय लिखकर भेजिए इस मेल आईडी पर nbtreader@timesgroup.com और सब्जेक्ट में लिखें-'भेजा फ्राई'

THE SPEAKING TREE
और पढ़ने के लिए देखें
hindi.speakingtree.in

बड़ा होना यानी ज़रूरतमंदों का मददगार बन जाना

प्रणव पण्ड्या

समय की मांग के हिसाब से दो तरह के दबाव इन दिनों निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। एक गैरजरूरी चीजों के लिए जुझन और दूसरा है- नवयुग की सृजन व्यवस्था को एक्टिवेट करने की जरूरत। व्यक्तिगत जिंदगी में भी ये दोनों कार्य अति कठिन हैं। फिर जहां देश, समाज या विश्व का प्रश्न है, वहां तो कठिनाई का अनुपात असाधारण होगा ही। प्रगति पथ पर अग्रसर होने के लिए उसके हिसाब से योग्यता और कर्मनिष्ठा उत्पन्न करनी पड़ती है। इनके बिना सामान्य स्थिति में रहते हुए किसी प्रकार दिन काटते रहना पड़ता है।

समस्याएं और कठिनाइयां सबके जीवन से जुड़ी हैं। लेकिन अलग-अलग श्रेणियों के लोग इनसे अलग-अलग तरह से जूझते हैं। पहली श्रेणी उन लोगों की है जिन्हें सामान्य कहा जाता है। ये कठिनाइयों से जूझ सकते हैं लेकिन क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसके बारे में वे अच्छी तरह विचार नहीं कर पाते हैं। वे साधनों के लिए, मार्गदर्शन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। यहां तक कि जीवन के लिए जरूरी साधन तक अपने लिए जुटाने में असमर्थ होते हैं। उनके लाभ-हानि के कारण दूसरे ही बने रहते हैं। दूसरा वर्ग वह है जो समझदार होते हुए भी संकीर्ण स्वार्थपरता से घिरा रहता है। योग्यता और तत्परता जैसी विशेषताएं होते हुए भी वे उन्हें मात्र लोभ, मोह, अहंकार की पूर्ति के लिए ही नियोजित किए रहते हैं। तीसरा वर्ग प्रतिभाशालियों का है। वे भौतिक क्षेत्र में कार्यरत रहते हैं, तो अनेक व्यवस्थाएं बनाते हैं। अनुशासन और दायरों से बंधे रहते हैं। बड़ी योजनाएं बनाते और चलाते हैं। जिन्होंने महत्वपूर्ण सफलताएं पाई हैं, प्रतियोगिताएं जीती हैं, उनमें ही मौलिक सूझ-बूझ होती है।

सबसे ऊंची श्रेणी देवमानवों की है, जिन्हें महापुरुष भी कहते हैं। वे प्रतिभाशाली होते हैं, पर उसका उपयोग आत्म परिष्कार से लेकर लोकमंगल तक के उच्च स्तरीय प्रयोजनों में ही किया करते हैं। समाज के निर्माण और समस्याओं के समाधान का श्रेय उन्हें ही जाता है। किसी देश की सच्ची संपदा वे ही समझ पाते हैं, जो अपने कार्यक्षेत्र को नंदन वन जैसा सुवासित करते हैं। बड़े कामों को बड़े शक्ति केंद्र ही संपन्न कर सकते हैं। दलदल में फंसे हाथी को बलवान हाथी ही खींचकर पार करते हैं। पटरी से उतरे इंजन को समर्थ क्रेन ही उठाकर उचित स्थान रखती है। समाज और संसार की बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए ऐसे ही वरिष्ठ प्रतिभावानों की आवश्यकता पड़ती है। प्रतिभाएं ऐसी सम्पदाएं हैं, जिनसे न केवल प्रतिभाशाली स्वयं भरपूर श्रेय अर्जित करते हैं, वरन अपने क्षेत्र, समुदाय और देश की अति विकट दीखने वाली उलझनों को भी सुलझाने में सफल होते हैं। इसी कारण भावनावश ऐसे लोगों को देवदूत तक कहते हैं।

जिस अवस्था में अभी दुनिया है, उसमें एक ओर महाविनाश का प्रलयंकर तूफान अपनी प्रचंडता का परिचय दे रहा है, तो दूसरी ओर सतयुगी नवनिर्माण की उमंगें भी उछल रही हैं। विनाश और विकास एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी हैं, तो भी उनके एक ही समय में अपनी-अपनी दिशा में चल सकना संभव है। इन दोनों के समन्वय को देखते हुए ही अपना समय युगसंधि का समय माना गया है।

जम्मू के जंगलों में वारदात कर रहे आतंकी, वहां भी मिला करारा जवाब

जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस साल सितंबर तक का वक्त दिया है। राजनीतिक दलों ने भी चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। BJP ने हाल ही में वहां अपनी कोर कमिटी की मीटिंग की। BJP की चुनाव को लेकर क्या तैयारी है और जम्मू-कश्मीर से उसे कितनी उम्मीद है, इस पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू-कश्मीर के पार्टी प्रभारी **तरुण चुग** से बात की **पूनम पाण्डे** ने। पेश हैं प्रमुख अंश :

विशुद्ध राजनीति इंटरव्यू

■ पिछले हफ्ते जम्मू-कश्मीर में BJP कोर कमिटी की मीटिंग हुई। क्या तैयारियां हैं BJP की वहां?

BJP वहां 50 के दशक के काम कर रही है। जनसंघ बनने से पहले वहां प्रेमनाथ डोगरा के नेतृत्व में प्रजा परिषद बनी थी। उसने जम्मू-कश्मीर के लोगों को मिलकर रहना चाहिए, हमें पाकिस्तान के हाथों में नहीं खेलना चाहिए- इस नैरेटिव पर काम किया था। BJP लगातार शांति और विकास की बात करती है। BJP वहां मजबूती से काम कर रही है। हमने लोगों का दिल जीता है। इस लोकसभा में विधानसभा के हिसाब से देखें तो 29 सीटें हमने जीती हैं। हम दो ही लोकसभा सीटों पर लड़े थे। इस बार हम पांचों लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ेंगे और BJP वहां बड़ी ताकत के रूप में उभरेगी। अब जम्मू-कश्मीर एक सकारात्मक राजनीति की ओर बढ़ा है। वहां के लोग विकास, विश्वास और शांति चाहते हैं। ये सब चीजें BJP ही दे सकती है।

■ वहां चुनाव अकेले लड़ेंगे या गठबंधन में?

BJP पूरी ताकत से वहां खड़ी है। हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं।

■ लोकसभा चुनाव में कश्मीर में तो BJP लड़ी ही नहीं। क्या यह संदेश नहीं गया कि आप जम्मू में ही मजबूत हैं, कश्मीर में नहीं?

जम्मू में हम पहले भी चुनाव लड़ते थे। कश्मीर में हम शांति इसलिए नहीं लाए कि वहां पर हमें चुनाव लड़ना है। हमने लोगों का दिल जीता और लोगों से कहा कि आप फैसला करें, कौन यहां लड़ेगा। जल्द ही हम वहां भी चुनाव लड़ेंगे। इस चुनाव में हम चाहते थे कि लोग ऐसा न समझें कि BJP अपने चुनाव लड़ने के लिए शांति या विकास लाई है। हमारे लिए जम्मू-कश्मीर हमारा आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है।

■ जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने से क्या फर्क पड़ा, क्या बदलाव दिखा?

जिस तरह DDC, BDC, पंचायत चुनाव हुए, लोगों ने निडर होकर वोट किया। आर्टिकल 370 खत्म करने के फैसले पर मुहर लगाई। इस बार लोकसभा चुनाव में लाखों लोगों ने वोट किया। यह वही जगह है जहां किसी जमाने में बॉयकॉट की राजनीति होती थी, जिसके सहारे लोग सत्ता में आते थे। इस बार हर मतदान केंद्र में रेकॉर्ड मतदान हुआ है। जम्मू-कश्मीर बदल रहा है। ये टेररिज्म कैपिटल की बजाय टूरिज्म कैपिटल बन रहा है। दो करोड़ टूरिस्ट पिछले साल जम्मू-कश्मीर आए, जो अपने आप में एक रेकॉर्ड है। तीन परिवार- गांधी-नेहरू परिवार, अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार, ये पहली बार सत्ता से बाहर हुए हैं। उमर अब्दुल्ला चुनाव हारे हैं, महबूबा मुफ्ती चुनाव हारीं, BJP ने दो प्रत्याशी खड़े किए थे- दोनों जीते।

■ मगर आतंकवाद पर तो लगाम नहीं लग पाई है..

जम्मू-कश्मीर में लगातार आतंकवादी घटनाओं पर हमने अंकुश लगाया है। आतंकवाद भी कम किया है, आतंकवादियों की आयु भी कम की है, उनकी संख्या भी कम की है, उनकी रिक्रूटमेंट भी कम की है। हमने आतंकवाद की समाप्ति के लिए साइंटिफिक तरीके से काम किया है। आतंकवाद को भी खत्म किया है और आतंकी संगठनों में नई भर्ती ना हो उसके लिए भी काम किया है। एक वक्त था जब पाकिस्तान नापाक खेल खेलता था और भारत के नागरिकों को बहलाकर उनका इस्तेमाल करता था। लेकिन अब वहां के नौजवान अपने हाथों से जम्मू-कश्मीर का भाग्य लिख रहे हैं।

■ लेकिन पिछले कुछ समय में जम्मू क्षेत्र में आतंकी वारदातें बढ़ी हैं। सैनिकों की शहादत हुई है। उन इलाकों में ये वारदातें हुई हैं जो सालों से शांत थे...

हर चुनाव में लोगों की भागीदारी, विकास होता देखकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI अपनी आखिरी बैटल लड़ रही है। सुरक्षा बल वहां लगातार कठोर कार्रवाई कर रहे हैं, उससे आतंकी बौखलाए और घबराए हुए हैं। आतंकियों ने अपनी वारदात के लिए जम्मू क्षेत्र के जंगलों को चुना है। कश्मीर में अब आतंकियों को कोई जगह नहीं मिल रही है तो उन्होंने जंगलों में अपनी जगह बनाने की कोशिश की है। लेकिन यहां भी उन्हें करारा जवाब मिला है। आतंकवादियों पर लगातार एक्शन हो रहा है। साफ है कि आतंकवाद किसी बदलाव दर्शाता नहीं होगा। जम्मू-कश्मीर को फिर उस दौर में नहीं जाने दिया जाएगा जहां कर्फ्यू, हड़ताल, सामूहिक हत्याएं, पलायन होता था।

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

■ ट्रंप की लोकप्रियता

15 जुलाई का संपादकीय 'बुलेट नहीं, बैलट' पढ़ा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप पर हुए हमले की जितनी निंदा की जाए कम है। तमाम विवादों के बावजूद डॉनल्ड ट्रंप लोकप्रियता के मामले में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। उनके समर्थकों का मानना है कि उनके नेता ट्रंप ही बेस्ट हैं। उन्हें भरोसा है कि वही अमेरिका को फिर से महान बना सकते हैं। हालांकि चुनाव नतीजे से ही यह पता चल पाएगा कि इस हमले से उन्हें कितनी सहानुभूति मिलती है। बहरहाल, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि लोकतंत्र में बैलट की ताकत ही बोलती है।

माम चंद सागर, इमेल से

■ सिस्टम में सुधार हो

2 जुलाई के लेख 'बारिश बोले तो, चाय-पकौड़े और अटेंक' में पढ़ने को मिला कि मुन्नाभाई ने सब कुछ छोड़-छाड़कर बारिश का आनंद लेने की सलाह दी। बरसात में चाय-पकौड़े की अहमियत तो बढ़ ही जाती है। हम अपने दृष्टिकोण और सोच को बदलकर मौसम और पर्यावरण की समस्याओं का सही तरीके से सामना कर सकते हैं। मुन्नाभाई, सर्किट और चिरकुट के माध्यम से दिखाया गया है कि हमें मौसम को दोष देने के बजाय अपनी गलतियों और सिस्टम की खामियों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए।

रमन श्रीवास्तव, इमेल से

■ उपचुनावों के नतीजे

हाल ही में सात राज्यों के 13 विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनावों में BJP को दो सीटें ही मिलीं, जबकि विपक्षी दलों को 10 सीटों पर शानदार जीत हासिल हुई है। इन उपचुनावों के माध्यम से कांग्रेस ने अपनी पुरानी जमीन फिर से हासिल करने की कोशिश की है। BJP को सबसे बड़ा झटका पश्चिम बंगाल में लगा है। TMC ने चारों सीटें बड़े अंतर से जीती हैं।

वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

nbtedit@timesgroup.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

कॉल रेट बढ़े, फिर भी 89% यूजर्स को कनेक्टिविटी की समस्या - खबर - अब WiFi से कॉल करने की आदत डालनी पड़ेगी!

रजनी गुप्ता

आर.एन.आई. नं. 310057/50 वार्षिकियां सुविधा: निर्दिष्ट अवधि के लिए संपूर्ण या आंशिक पुनर्भुगतान सुविधा: उपेक्षित। लाभांशधारी बैंक: बोनस्पेस एवम बचतों निर्देशक के लिए उपलब्ध पत्राचार हेतु, 7 अशोकनगर रायल मार्ग, नई दिल्ली-110022 से प्रकाशित तथा **राहुल अनिल द्विवेदी** प्रिंट, मयूर 2ए, **अंसारीनगर ईस्ट नयी दिल्ली** 110 029, प्रिंटर्स 34-11, इंडस्ट्रीज एरिया उदयपुर, कालिंदी, कॉलोनी, दक्षिण के मुद्रित। फोन : 23320000 फैक्स: 23400207, रजिस्ट्रेड कार्यालय : टाइम्स मीडिया टेक, पृष्ठ-400001। नियत प्रेस मुख्य : 1 ए. डी. सोसाईटी, नेहरू के मुख्य : औरंगाबाद 3 औरंगाबाद : रेलवे 2 के., औरंगाबाद : रेलवे के 4 संपादक (हिन्दी संस्करण) : आलोक भट्टाचार्य (इस अंक में प्रकाशित समाज सामग्री के भारत एवं संपादन हेतु वी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी)

उपचुनाव परिणाम

'इंडिया' को बढ़त

सात राज्यों में हुए उपचुनाव परिणामों में 'इंडिया' समूह को 13 में से 10 पर विजय मिली, जबकि भाजपा केवल दो सीटों पर सफल हुई। इस प्रकार हाल ही में सात राज्यों में हुए उपचुनाव में 'इंडिया' समूह को लाभ हुआ है। इस नतीजे के महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव हो सकते हैं। समय आ गया है कि भाजपा आत्मनिरीक्षण कर पता लगाए कि क्या मतदाताओं से उसका संवाद कमजोर हो रहा है या राज्यों के स्तर पर राजनीतिक व चुनावी गणित में कोई बदलाव हो रहा है? विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियों के गठबंधन 'इंडिया' ने दिखा दिया है कि वह एक मजबूत शक्ति है और उसकी यह स्थिति संभवत: बनी रहेगी। वैसे आमतौर से माना जाता है कि उपचुनाव राज्य में सत्तारूढ़ दल के पक्ष में जाते हैं और इस दृष्टिकोण से विपक्ष शासित राज्यों में 'इंडिया' की विजय स्वाभाविक लगती है। उपचुनावों में सबसे बड़ी विजेता तृणमूल कांग्रेस-टीएमसी है। उसने अपने राज्य में उपचुनाव वाली सभी चार सीटों पर विजय पाई है। इस विजय से राज्य में टीएमसी का प्रभुत्व स्पष्ट होता है राज्य की जनता के बड़े हिस्से का ममता बनर्जी के नेतृत्व पर विश्वास प्रकट होता है। इससे यह भी स्पष्ट है कि राज्य में भाजपा अपना इच्छानुकूल विस्तार करने में विफल रही है। हालांकि, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि टीएमसी भले ही राष्ट्रीय स्तर पर 'इंडिया' का हिस्सा हो, पर वह बंगाल में कांग्रेस और माकपा के लिए कोई स्पेस छोड़ने को तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में 'इंडिया' समूह के संयुक्त प्रयासों से शिवसेना-उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट को विजय मिली है और उसने राज्य में अपनी स्थिति मजबूत की है। उपचुनाव

परिणाम ने शिवसेना, कांग्रेस तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-रांकापा गठबंधन को मजबूत किया है। लोकसभा चुनाव के कुछ ही समय बाद हुए इन उपचुनाव परिणामों से स्पष्ट है कि मतदाताओं की वह प्रवृत्ति बनी हुई है जिसके चलते उन्होंने विपक्ष को तुलनात्मक रूप से मजबूत किया है तथा भाजपा को थोड़ा झटका दिया है। भाजपा को कर्नाटक में कांग्रेस से मुकाबला करना पड़ रहा है, जबकि कांग्रेस राजस्थान में भी सफल रही है। भाजपा को उत्तराखंड में तगड़ा झटका लगा है जहां उसने लगातार तीसरी बार लोकसभा की सभी सीटों पर विजय पाई है। उत्तराखंड में अभूतपूर्व ढंग से पुष्कर सिंह धामी दूसरी बार प्रदेश में सरकार बनाने में सफल हुए थे। वैसे बद्रीनाथ विधानसभा सीट पहले कांग्रेस का गढ़ रही है, पर कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा के पुराने मतदाता और कार्यकर्ता पार्टी में आने वाले नए लोगों से संतुष्ट नहीं थे। उपचुनावों में भाजपा को केवल दो सीटें मिलने से स्पष्ट है कि उसे अपनी रणनीति पुन: बनानी होगी तथा राष्ट्रीय मुद्दों के साथ ही स्थानीय मुद्दों को ज्यादा प्राथमिकता देनी होगी। इसके साथ ही आने वाले महीनों में स्पष्ट होगा कि विपक्षी 'इंडिया' समूह अपनी एकजुटता बनाए रखने में सफल होता है या नहीं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की मदद करने वाली समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 'इंडिया' गठबंधन सहयोगी के रूप में उतरने की इच्छा जताई है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि यदि उनको समुचित संख्या में सीटें न दी गईं तो सपा अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी। भाजपा लोकसभा चुनाव परिणामों का गंभीर विश्लेषण कर रही है। वह उपचुनाव परिणामों का भी विश्लेषण कर समुचित सबक लेगी। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि उपचुनाव परिणामों का कुछ समय बाद होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों पर क्या प्रभाव पड़ेगा तथा 'इंडिया' व भाजपा नीत 'राजग' इस बीच कैसी तैयारी करते हैं।

आर्थिक विभीषिका से बचा भारत

हालांकि, अपने दम पर बहुमत न मिलने से भाजपा दबाव में है, पर यदि कांग्रेस नीत 'इंडिया' सरकार बनाने में सफल होता तो भारत को भयानक आर्थिक विभीषिका का सामना करना पड़ता।

उत्तम गुप्ता
(लेखक, नीति विश्लेषक हैं)

चार जून को लोकसभा चुनाव, 2024 परिणाम आने के बाद केन्द्र 'राजकोषीय विभीषिका' की स्थिति से बचने में सफल हुआ है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा अपने दम पर पूर्ण बहुमत प्राप्त करने में विफल रही, पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन-राजग के 53 सांसदों के साथ 293 सांसद जुटा कर वह बहुमत पाने में सफल हुई तथा सरकार बनाई। दूसरी ओर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' कुल 234 सांसदों का समर्थन ही प्राप्त कर सकी। यदि 'राजग' के केवल 38 सांसद 'इंडिया' समूह में चले जाते तो वह सत्ता तक पहुंच जाती। इस परिदृश्य में कांग्रेस को अप्रैल, 2024 में जारी अपने चुनाव घोषणापत्र-'न्याय पत्र' में किए गए वादे-गारंटियां पूरी करनी पड़तीं। इनका राजकोष पर भारी बोझ पड़ता। 'महालक्ष्मी' योजना के अंतर्गत प्रत्येक गरीब भारतीय परिवार को हर साल 100,000 रुपये अनुदान की बात पर गौर करें। यह बिना शर्त के आर्थिक सहायता सीधे परिवार की सबसे वृद्ध महिला के खाते में जानी थी। यदि परिवार में महिला न होती तो इस धनराशि को परिवार के सबसे वृद्ध व्यक्ति के खाते में जाना था। एक चुनावी रैली में राहुल गांधी ने घोषणा की थी, 'शुरुआत में हम आपको 100,000 रुपये वार्षिक देंगे, जबकि बाद में हम यह राशि बढ़ा कर 2,00,000 भी कर सकते हैं।' भारत में लगभग 400 मिलियन परिवार हैं। यदि हम इन परिवारों में केवल 10 प्रतिशत को ही गरीब मानें तो उनकी संख्या 40 मिलियन होती है। इस प्रकार इस योजना से सरकारी खजाने पर हर साल 400,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ता। यदि यह अनुदान बढ़ा कर 200,000 कर दिया जाता तो यह खर्च बढ़ कर हर साल 800,000 करोड़ हो जातज़।

बजट पर इसके कारण पड़ने वाले भारी प्रभाव को देखते हुए घोषणापत्र में योजना के साथ दो शर्तें लगाई गई थीं। पहला, 'गरीब की पहचान आय पिरामिड के सबसे नीचे वाले परिवारों के आधार पर होगी।' दूसरा, 'इस योजना को चरणों में लागू किया जाएगा तथा हर साल लाभार्थी परिवारों की समीक्षा की जाएगी तथा गरीबी उन्मूलन पर इसके प्रभाव का आंकलन होगा।' ये शर्तें इस आधार पर परिभाषित की गई थीं कि शुरुआत में सभी 40 मिलियन परिवारों को इसमें शामिल नहीं किया जाता। इसके साथ ही पार्टी बोझ को देखते हुए कुछ लाभार्थियों को छोड़ सकती थी। लेकिन योजना के अंतर्गत मिलने वाली भारी धनराशि को देखते हुए एक भी गरीब परिवार एक बार लाभार्थी परिवार के दायरे में शामिल होने के बाद किसी प्रकार उससे बाहर न जाना चाहता। ऐसा करने का कोई भी प्रयास भारी सामाजिक-आर्थिक तनाव का कारण बनता तथा लाभार्थियों व उनसे वंचित लोगों के बीच टकराव होता। इस कारण सभी 40 मिलियन गरीब परिवारों को हर साल 200,000 लाख रुपये न मिलते।

कांग्रेस की अन्य गारंटियों में 'युवा अप्रेंटिसशिप योजना'-वाईएएस शामिल थी जिसके अंतर्गत प्रत्येक डिप्लोमाधारक बेरोजगार नौजवान को हर साल 100,000 रुपये मिलने थे। वर्तमान समय में 15-29 वर्ष आयुवर्ग के कुल 260 मिलियन युवा हैं और बेरोजगारी दर 10 प्रतिशत है। यदि सभी 26 मिलियन बेरोजगार युवाओं को 100,000 रुपये सालाना दिए जाते तो इससे खजाने पर हर साल 260,000 करोड़ का बोझ पड़ता। 'अप्रेंटिसशिप' एक प्रकार की व्यवस्था है जिसके अंतर्गत किसी युवा को एक समय तक नया कौशल सिखाया जाता है ताकि वह एक उपयुक्त रोजगार या नौकरी प्राप्त कर सके। इस कालखंड में उसे स्टाइपेंड के रूप में एक निश्चित धनराशि मिलती है। तार्किक रूप से इस व्यवस्था में प्रशिक्षण काल समाप्त होने के बाद स्टाइपेंड की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने इसकी कोई रूपरेखा नहीं दी थी कि प्रशिक्षण और उसके बाद अप्रेंटिसशिप पूरी कर चुके युवाओं को किन बिजनेसों में स्थान मिलेगा। ऐसे परिदृश्य में हर साल 100,000 रुपये प्राप्त करने वाला नौजवान हमेशा वैसा ही बना रहता। इसके परिणामस्वरूप केन्द्र को लगातार हर साल 260,000 करोड़ रुपये का बोझ उठाना पड़ता।कांग्रेस ने न्यूनतम समर्थन मूल्य-एमएसपी की कानूनी गारंटी का वादा किया था। किसन इसे उन सभी 26 फसलों के लिए चाहते थे जिन पर वर्तमान समय में एमएसपी दिया जाता है। अंतत: यह सभी फसलों, यानी सभी कृषि उत्पादों पर लागू होता। सरकार निजी क्षेत्र को एमएसपी पर खरीद के लिए बाध्य नहीं कर सकती, इसलिए उसे सारी फसलें खरीदनी पड़तीं। इससे हर साल खजाने पर 33,00,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ता। कांग्रेस ने 3 मिलियन सरकारी नौकरियों का वादा किया था। यदि औसत वेतन हर महीने 50,000 रुपये मान लिया जाए तो इसे खजाने पर 180,000 करोड़ का बोझ हर साल पड़ता। यदि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून-मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी बढ़ा कर 400 रुपये प्रति दिन कर दी जाए तो इससे लगभग 80,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। कांग्रेस ने छात्रों को एक बार कर्ज माफी का वादा भी किया था जिससे लगभग 120,000 करोड़ का बोझ पड़ता। इस प्रकार यदि कुल मिला कर देखा जाए तो कांग्रेस की 'गारंटी योजनाओं' से केन्द्र सरकार पर हर साल 47,40,000 करोड़ रुपये का असाधारण बोझ पड़ता। यदि एक बार छात्रों को माफ किए जाने वाले कर्ज का बोझ छोड़ दिया जाए तो इससे हर साल खजाने पर 46,20,000 करोड़ का बोझ पड़ता।

यह धनराशि 2024-25 के अंतरिम केन्द्रीय बजट में प्रस्तावित 47,66,000 करोड़ रुपये के लगभग बराबर है। इसके साथ ही यह 11,00,000 करोड़ रुपये के पूंजीगत खर्च से चार गुना अधिक है। 2024-25 में केन्द्र सरकार की कर्ज के अलावा कुल प्राप्तियां लगभग 30,80,000 करोड़ थीं। इनमें करों से होने वाली प्राप्तियां 26,02,000 करोड़ हैं। इस प्रकार केवल बहु-प्रचारित 'महालक्ष्मी' योजना पर होने वाला खर्च सारी प्राप्तियों तथा लगभग एक तिहाई कर प्राप्तियों को अपने भीतर समेट लेता। वर्तमान समय में राजकोषीय घाटा 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद-जीडीपी का 5.1 प्रतिशत है। यदि इसमें 'कांग्रेसी गारंटियों' का अतिरिक्त खर्च जोड़ लिया जाए तो यह जीडीपी का 19.1 प्रतिशत हो जाएगा। यह 2020-21 में हुए 9.2 प्रतिशत घाटे से दूना है, जब अर्थव्यवस्था विनाशकारी कोरोनावायरस वैश्विक महामारी के दुष्प्रभाव से पंगु हो गई थी। यह सोच कर ही भय पैदा हो जाता है कि कांग्रेस की सभी 'गारंटियां' लागू होने के बाद केन्द्र का खर्च लगभग 187,35,000 करोड़ हो जाता। वर्तमान समय में केन्द्र का कर्ज जीडीपी का 57 प्रतिशत है।

राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन कानून-एफआरबीएम में संशोधन के बाद इसे 2024-25 में घटा कर 40 प्रतिशत किया जाना है। इसके बजाय हम 100 प्रतिशत से अधिक की ओर बढ़ रहे हैं। भारत के मजबूत आर्थिक आधारों, जीवन्त वृद्धि गतिशीलता तथा राजकोषीय मजबूती पर ध्यान देने से वैश्विक रेटिंग एजेंसियों, जैसे एसएंडपी ने हमारी सावरेन रेटिंग बढ़ाई है। इससे देश लगभग डेढ़ शताब्दी बाद 'स्थिर' से 'सकारात्मक' श्रेणी में आने में सफल हुआ है। यदि दुर्भाग्य से 'कांग्रेसी गारंटियां' लागू हो जातीं तो 'राजकोषीय व्यावहारिकता' मिट्टी में मिल जाती। ऐसी स्थिति में राजकोषीय विभीषिका पैदा होती, कर्ज बेलगाम हो जाता, ब्याज की दरें आसमान छूने लगतीं, मुद्रास्फीति बहुत बढ़ जाती, निवेश घट जाता तथा आर्थिक गतिविधियां कम हो जातीं। 'कांग्रेसी गारंटियों' यज्ञ 'खैरातों' के कारण करोड़ों लोगो को कमाने की जरूरत न रहती और वे अपनी सभी जरूरतें पूरी करने के लिए सरकारी खैरातों की ओर देखते रहते। संक्षेप में इससे भारत 'आर्थिक विनाश' की ओर आगे बढ़ता। हालांकि, अपने दम पर पूर्ण बहुमत न मिलने से भाजपा दबाव में है, पर यदि कांग्रेस नीत 'इंडिया' समूह को सत्ता मिल जाती तो भारत निश्चित रूप से आर्थिक विनाश का शिकार बन जाता।

इच्छाओं से मुक्ति की कला

> बुद्ध ने चार अवधारणाओं की वकालत की- शरीर का निरीक्षण करें, संवेदनाओं का निरीक्षण करें, मन के प्रवाह का निरीक्षण करें, अपने वास्तविक स्वभाव का निरीक्षण करें

रवि वलूरी
(लेखक, रेलवे विभाग से संबंधित हैं)

एक बार एक मस्तिष्क भौतिक विज्ञानी रहते थे जो एक सम्मानित विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। प्रोफेसर को पुरस्कारों से सम्मानित किया गया और दुनिया भर में उनकी पहचान बनी। जैसे-जैसे वे एक मशहूर हस्ती बनते गए, उनका सिर जल्दी ही फूलने लगा। उनका दिखावा उनका अहंकार बन गया। सरकार और प्रशासन ने उन्हें दिए जाने वाले सभी पुरस्कारों को छीन लिया और उनकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि वे शराबी बन गए थे। सम्मानित प्रोफेसर जीवन में इन दुर्घटनाओं से जूझने में असमर्थ थे।

उनके बिरादरी के कुछ शुभचिंतकों ने उनके साथ सहानुभूति जताई और अपने एक समय के तेजस्वी सहयोगी के लिए करुणा से भर गए। भौतिक विज्ञानी को एक पुनर्वास केंद्र में ले जाया गया और एक विषहरण आहार के तहत धीरे-धीरे शराब और नशीली दवाओं से छुटकारा दिलाया गया। उन्होंने हैप्पीनेस प्रोग्राम से गुजरा और अनोखी लयबद्ध साँस लेने की तकनीक सीखी जिसने उनके ठीक होने के लिए सहारा प्रदान किया। हालाँकि प्रोफेसर अब शांत हो चुके थे और उनकी भोगवादी प्रवृत्तियाँ समाप्त हो चुकी थीं, फिर भी वे भीतर से तृप्त महसूस कर रहे थे। उनकी आत्मा अभी भी तृप्त नहीं हुई थी। उन्होंने जीवन और ब्रह्मांड के आध्यात्मिक आयाम में गहरी रुचि विकसित की। इस प्रकार, प्रोफेसर ने आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। यात्रा उन्हें दुनिया के आधे हिस्से में ले गई, जब तक कि वे हिमालय में एक सुदूर गाँव में एक सिद्ध गुरु के चरणों में नहीं पहुँच गए।

विभिन्न धर्मों के पवित्र ग्रंथों के इस अधिपति ने ज़ेन बौद्ध धर्म में उल्लेखनीय निपुणता और गुण प्राप्त किया था। गेरू के वस्त्र पहने पवित्र व्यक्ति ने प्रोफेसर का गर्मजोशी से स्वागत किया। उनकी खोजी और चमकदार आँखें प्रोफेसर को देख रही थीं। भौतिक विज्ञानी ने अपनी कहानी सुनाई।

जब तक तुम अपने अहंकार और आत्म-दंभ को उसी तरह नहीं छोड़ देते जैसे चाय कप से छलकती है, तुम कभी भी कुछ नया नहीं सीख पाओगे। जब तुम गुरु के पास जाओ तो अपनी सारी इच्छाएँ छोड़ दो। अपना बोझ छोड़ दो।

उन्होंने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला कि वे अब आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ब्रह्मांड के गर्भ में छिपे रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यही तो आप विश्वविद्यालय में और अपनी प्रयोगशाला में कर रहे थे, है न प्रोफेसर? द्रष्टा ने पूछा।उन्हें लगा कि ज़ेन मास्टर उनके जीवन से गायब चिंगारी को प्रज्वलित कर सकते हैं और उनके मन से द्वेषपूर्ण विचारों को दूर करने में उनकी मदद कर सकते हैं ताकि वे पिरामिड को उलट सकें। वह एक बार निराशा के भंवर से सफलतापूर्वक बाहर निकल आया था और सुरंग के अंत में उसे रोशनी दिखाई दे रही थी। फिर भी उसके जीवन में कुछ कमी थी!

वह पेड़ की शाखाओं से गिरने वाले पतझड़ के पत्ते की तरह सूखा था। जिस समय तुम मुक्त होते हो तो, तुम क्या नया जानने की कोशिश कर रहे हो? ठीक है, चलो एक कप चाय पीते हैं, पूज्य आत्मा ने कहा। जब उस समझदार और बुद्धिमान आत्मा ने चाय डाली तो प्रोफेसर सहज दिखाई दिए। जल्द ही कप छलकने लगा। यह देखकर प्रोफेसर ने कहा, पवित्र महोदय, कप छलक रहा है! बिल्कुल, और मैं आपकी प्रतिक्रिया की जांच कर रहा था, पवित्र व्यक्ति ने टिप्पणी की। जब तक तुम अपने अहंकार और आत्म-दंभ को उसी तरह नहीं छोड़ देते जैसे चाय कप से छलकती है, तुम कभी भी कुछ नया नहीं सीख पाओगे। यही रहस्य है, ज़ेन मास्टर ने बिल्कुल तथ्यात्मक तरीके से कहा। जब तुम गुरु के पास जाओ तो अपनी सारी इच्छाएँ छोड़ दो। अपना बोझ छोड़ दो, उन्होंने कहा। ज़ेन मास्टर ने आगे कहा, बुद्ध ने चार अवधारणाओं की वकालत की- शरीर का निरीक्षण करें (कायाना पास्काना) संवेदनाओं का निरीक्षण करें (वेदानु पास्काना) मन के प्रवाह का निरीक्षण करें (चित्तना पास्काना) अपने वास्तविक स्वभाव का निरीक्षण करें (धम्मानु पास्काना)। प्रोफेसर को रहसास हुआ कि वह अपने मन को समझे बिना ही अज्ञात क्षेत्रों में प्रवेश कर गया था। उसका मन राक्षसी और अहंकारी विचारों से भरा हुआ था और वह कठोर हो गया था। वह न तो सरल था, न ही विनम्र या जागरूक। ये उसके लिए जाने और शुद्ध और स्पष्ट होने की कुंजी थे।

आप की बात

जनसंख्या वृद्धि

विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर भारत सरकार की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश के 36 में से 31 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों ने टोटल फर्टिलिटी रेट-टीएफआर को रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 प्रतिशत से नीचे लाने में कामयाबी हासिल कर ली है। इसका अर्थ है कि अब इन राज्यों में जनसंख्या बढ़ने के बजाय घटेगी। फर्टिलिटी रेट्स का नियंत्रित होना भारत जैसे देश के लिए अत्यावश्यक था। मगर धर्म के आधार पर देखा जाए तो आबादी की बढ़ोतरी में यह गिरावट मोटेतौर से हिंदुओं में ज्यादा आई है। हालांकि, आजादी के बाद मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि भी थोड़ी घटी है, पर यह अब भी हिंदुओं व अन्य समुदायों की तुलना में बहुत अधिक है। जनसंख्या वृद्धि से देश की 140 करोड़ की आबादी के सामने सारे संसाधन बौने पड़ गए हैं। इसे देखते हुए संतति नियंत्रण कानून लाने की अब भी जरूरत है। एक या दो बच्चे वाले अनेक मध्यवर्गीय परिवार कोई मुफ्त सुविधा नहीं लेते हैं और सरकार को टैक्स देते हैं। इसके उलट अधिक संतानों वाले अनेक परिवार सभी मुफ्त सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकारी सुविधायें व सरकारी नौकरियां केवल छोटे परिवारों तक सीमित की जानी चाहिए।

-सुभाष बुड़ावन वाला, रतलाम

ट्रंप पर हमला

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पर किये गए हमले की जितनी निंदा की जाय वह कम है। यह लोकतंत्र पर हमला है और इसका कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मगर यह देखना भी जरूरी है कि आज दुनिया भर में राजनीति चर्चस्ववादी हो गई है। इसके कारण अनेक देशों में नेताओं और जनता के बीच न केवल दूरियां बढ़ रही हैं, बल्कि जनता के अनेक तबके और लोग व्यक्तिगत रूप से नेताओं को अपना दुश्मन मानने लगे हैं। इस कारण ट्रम्प पर हमला करने वाले 20 वर्षीय किशोर की मन:स्थिति भी समझी जानी चाहिए। कहा जा रहा है कि हमलावर रिपब्लिकन पार्टी का ही वोटर था और डोनाल्ड ट्रम्प की कथित विभाजनकारी नीति का विरोधी था। वैसे भी अमेरिकी समाज में हिंसा और बंदूक की संस्कृति काफी गहरे तक जड़ें जमा चुकी है। ट्रंप पर हमला अमेरिका में फिर बंदूक नियंत्रण कानून की आवश्यकता प्रदर्शित करता है, लेकिन विडंबना है कि स्वयं ट्रंप और उनकी पार्टी हमेशा से बंदूक-नियंत्रण के खिलाफ रही है। इस हमले से कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों की हत्या तथा कई पर हुए हमलों की यादें फिर ताजा हो गई हैं। देखना होगा कि इसका अमेरिकी चुनाव तथा ट्रंप की विजय की संभावनाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है।

- जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर

संविधान हत्या दिवस

सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का ऐलान किया है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस सहित सारे विपक्षी दलों का गठबंधन- इंडिया संविधान बचाओ व लोकतंत्र बचाओ के नारे संसद से सड़क तक लगाता रहा है। 25 जून, 1975 को वास्तव में संविधान और लोकतंत्र की हत्या हुई थी, विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, अखबारों के मुंह पर ताले लगा दिए गए थे और यहाँ तक कि आम लोगों में भी यदि कोई सरकार के विरूद्ध बोलता पाया गया तो उसे भी जेल में बंद कर दिया जाता था। पूरे 19 माह सरकार की तानाशाही चली। इंडिया समूह के अनेक नेता भी उस समय प्रताड़ित हुए थे, पर आज संकुचित राजनीतिक व चुनावी स्वार्थ के कारण उनको यह याद नहीं आ रहा है। आज वे अघोषित आपातकाल की बात करते हैं, लेकिन पिछले 10 वर्षों में न तो मीडिया पर सेंसरशिप लगी न नेताओं की बोलने की आजादी पर प्रतिबन्ध लगे और न विरोधी दलों के नेताओं को बंद किया गया। भाजपा सरकार ने न संविधान या लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया और न आरक्षण खत्म करने का प्रयास किया। ऐसे में कटु यथार्थ से मुंह चुराने वाले विपक्षी अनर्गल प्रलाप का कोई अर्थ नहीं है और जनता यह असलियत समझ रही है।

शकुंतला महेश नेनावा, इंदौर

एलजी को अधिक शक्ति

कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर प्रदेश के उप-राज्यपाल-एलजी को अधिक शक्तियां दे दी हैं। मोटौतौर से दिल्ली के एलजी की लगभग सभी शक्तियां तरह जम्मू कश्मीर के एलजी को दी गई हैं। केंद्र सरकार का यह निर्णय अनेक कारणों से प्रशंसनीय है। जम्मू कश्मीर की विशिष्ट स्थिति को देखते हुए तथा वहां हालिया लोकसभा चुनाव में रिकार्डतोड़ मतदान के बावजूद केन्द्र सरकार प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा वहां पैदा होने वाली संभावित समस्याओं के बारे में फूंक-फूंक कर कदम रख रही है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को पुलिस पर अधिकार तथा कर्मचारियों के स्थानान्तरण के संबंध में अधिकार दिए गए हैं। इनका उद्देश्य राज्य में सेना व अर्धसैनिक बलों के साथ ही पुलिस का बेहतरीन तालमेल बैठाना तथा अधिकारियों की स्थानान्तरण शक्ति से राज्य के सभी भागों का समुचित व समन्वित विकास सुनिश्चित करना है। विडंबना है कि जम्मू कश्मीर की ऐसी शक्तियां इस बदलाव पर हायतोबा मचा रही हैं जो अब तक राज्य को अपनी जागीर समझती थीं।

- मनमोहन राजावत, शाजापुर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

युद्ध तब होता है, जब संवाद के सारे रास्ते खत्म हो जाते हैं।
-मार्गरेट एटवुड

आगामी 23 जुलाई को पेश हो रहे पूर्ण बजट से ऐन पहले सीबीडीटी के आंकड़ों से शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में भारी वृद्धि का पता चलना सरकारी खजाने के लिए शुभ संकेत तो है ही, देश की मजबूत होती अर्थव्यवस्था के प्रति भी आश्वस्त करने वाला है।

शुभ संकेत

आम बजट के पेश होने के ऐन पहले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा जारी आंकड़ों में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में 19.54 फीसदी की वृद्धि दर्ज हुई है, जो सरकार की मजबूत होती वित्तीय स्थिति को तो दर्शाता ही है, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर भी सकारात्मक संकेत देता है। रिफंड की राशि भी पिछले वित्त वर्ष की तुलना में करीब साढ़े चौंसठ फीसदी ज्यादा रही, जो करदाताओं को समय पर राहत देने की सरकार की दक्षता को ही दर्शाती है। उल्लेखनीय है कि सीबीडीटी ने ये आंकड़े वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जारी किए हैं, जिनके अनुसार, शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह बढ़कर 5.74 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है, जो पिछले वित्त वर्ष में 4.80 लाख करोड़ रुपये था। इसमें 2.1 लाख करोड़ रुपये का कॉरपोरेट कर व 3.46 लाख करोड़ रुपये का व्यक्तिगत आयकर भी शामिल है। दरअसल, इस वृद्धि का श्रेय सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों में लाए गए विभिन्न सुधारों व नीतिगत बदलावों को भी जाता है, जिनकी बदौलत ही देश में आयकर भरने वालों की संख्या पिछले दस वर्षों में दोगुनी हुई है। इसके अतिरिक्त, जीएसटी के प्रभावी क्रियान्वयन और आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाने जैसे उपायों ने करदाताओं को प्रोत्साहित किया, तो डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने और काले धन पर नियंत्रण के प्रयासों ने भी कर संग्रह में वृद्धि की है। हालांकि, वित्त वर्ष 2022-23 में देश के करीब 140 करोड़ लोगों में से सिर्फ 2.24 करोड़ लोगों ने ही आयकर दिया। देश में शून्य आयकर देनदारी वाले आईटीआर की संख्या का बढ़ना भी एक चिंताजनक पहलू है, जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सरकार आगामी 23 जुलाई को 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश करने जा रही है, ऐसे में प्रत्यक्ष कर संग्रह में आया उछाल राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखने में तो मदद करेगा ही, इससे सरकार को अधिक वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध होंगे,

जिनका उपयोग देश में बुनियादी ढांचे के विकास, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किया जा सकेगा। इससे न केवल वर्तमान में, बल्कि दीर्घकालिक दृष्टि से भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। कुल मिलाकर, प्रत्यक्ष कर संग्रहण में बढ़ोतरी दर्शाती है कि आर्थिक सुधार के लिए उठाए जा रहे कदम सही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन यह वृद्धि स्थायी हो, इसके लिए जरूरी है कि आर्थिक नीतियों में स्थायित्व बना रहे, व्यापार व निवेश के माहौल को ज्यादा अनुकूल बनाया जाए और कर प्रशासन में पारदर्शिता व सुगमता सुनिश्चित करने के प्रयास लगातार होते रहें।

नाटो को बदलना होगा

वर्ष 1951 में नाटो के बारे में कहा गया था कि अगर दस वर्षों में राष्ट्रीय रक्षा उद्देश्यों के लिए यूरोप में तैनात सभी अमेरिकी सैनिकों को वापस नहीं भेजा गया, तो यह पूरी परियोजना विफल हो जाएगी। लेकिन इसकी स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने पर भी यूरोप में लगभग 90 हजार अमेरिकी सैनिक तैनात हैं।

अमेरिका के 34वें राष्ट्रपति और नाटो के तहत यूरोप में मित्र देशों की अभियान सेना के पहले सर्वोच्च कमांडर जनरल ड्वाइट आइजनहावर का दृढ़ विश्वास था कि उनका मिशन यूरोपीय लोगों को अपनी सैन्य ताकत के बल पर खड़ा करना था, न कि अमेरिकी सैनिकों को ब्रुसेल्स एवं बर्लिन का स्थायी अंगरक्षक बनाना।

वर्ष 1951 में उन्होंने नाटो के बारे में लिखा था, यदि दस वर्षों में राष्ट्रीय रक्षा उद्देश्यों के लिए यूरोप में तैनात सभी अमेरिकी सैनिकों को वापस नहीं भेजा गया, तो यह पूरी परियोजना विफल हो जाएगी।' लेकिन विगत नौ जुलाई को जब नाटो सहयोगी देशों के नेता उसकी 75वीं वर्षगांठ के लिए वाशिंगटन में सम्मिलित हुए, उस समय भी जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और अन्य स्थानों पर लगभग 90 हजार अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, जो पांच लाख सैनिकों वाले नाटो के सैन्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नाटो में अमेरिका की व्यापक मौजूदगी सिर्फ सैनिकों की बड़ी संख्या के कारण नहीं है, बल्कि यूक्रेन सपोर्ट ट्रैकर डाटाबेस के मुताबिक, दुनिया भर के देशों द्वारा यूक्रेन को आवंटित 206 अरब डॉलर की सैन्य व असैन्य सहायता राशि में से 79 अरब डॉलर की सहायता अकेले अमेरिका ने दी है। कैटो इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार, 1960 के बाद से मित्र देशों के सकल घरेलू उत्पाद में अमेरिका की हिस्सेदारी औसतन लगभग 36 प्रतिशत रही है, जबकि मित्र देशों के सैन्य खर्च में इसकी हिस्सेदारी 61 प्रतिशत से अधिक रही है।

फराह स्टॉकमैन
द न्यूयॉर्क टाइम्स

लेकिन, अब यह स्पष्ट है कि यूरोपीय देशों को अपनी रक्षा के लिए ज्यादा जिम्मेदारी उठानी होगी। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी का अलगाववादी धड़ा इस बिंदु पर अमीर यूरोपीय देशों को आड़े हाथ लेते हैं कि ये देश सामाजिक सुरक्षा पर अमेरिका से भी ज्यादा खर्च करते हैं, लेकिन इनके पास अपनी सेना के लिए पैसे नहीं हैं। बल्कि, इसलिए भी कि अमेरिकी अधिकारी अब चीन द्वारा पेश की

गई चुनौतियों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिसके लिए आने वाले वर्षों में अधिक संसाधनों की जरूरत होगी, खासकर चीन, रूस, उत्तर कोरिया और ईरान के बढ़ते सहयोग को देखते हुए। अमेरिका हर जगह एक साथ, अकेले सब कुछ नहीं कर सकता। नॉर्वे के विदेश मंत्री एस्पेन बार्थ ईडे ने बताया कि अमेरिकी चुनाव में चाहे जो भी जीते, यूरोपीय नेता समझते हैं कि उन्हें और अधिक योगदान देने की आवश्यकता है। वाशिंगटन की अपनी हालिया यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि रिपब्लिकन नेतृत्व ने बताया कि यूरोपीय लोगों को यूक्रेन में युद्ध के लिए बहुत अधिक जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि अमेरिका के पास 'और भी बड़े काम हैं।'

इसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन उतनी तेजी से नहीं, जितनी होनी चाहिए। नाटो शिखर सम्मेलन की निस्संदेह यह उपलब्धि रही कि 23 नाटो सदस्यों ने अपने जीडीपी का कम से कम दो फीसदी अपनी सेना पर खर्च करने पर कुछ हद तक सहमति जताई, जबकि एक दशक पहले तक मात्र तीन सदस्य ही इतना खर्च करते थे। लेकिन आश्चर्यजनक है कि नाटो के 32 सदस्यों में से एक तिहाई अब भी खर्च के उस लक्ष्य से पीछे हैं, जिस पर 2014 में सहमति बनी थी। अगर रूस ने पूर्ण पैमाने पर हमला किया और नाटो सदस्य और खर्च करने के लिए राजी नहीं हुए, तो यह कल्पना करना मुश्किल है कि क्या होगा।

इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल अफेअर्स के ताजा सर्वे के मुताबिक, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस एवं जर्मनी में अधिकांश लोगों का मानना है कि यूरोप को नाटो में बनाए रखने के लिए उन्हें अपनी रक्षा के लिए प्रमुख जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अमेरिका पर यूरोप की निर्भरता महाद्वीप में बढ़ती बेचैनी को जन्म दे रही है। दरअसल, इसका एक कारण मानवीय स्वभाव है। अगर उनकी रक्षा के लिए हमेशा अमेरिका खर्च वहन करता है, तो सहयोगी क्यों निवेश करेंगे? लेकिन दूसरा कारण संरचनात्मक है। जब नाटो का गठन हुआ था, तो यूरोपीय सहयोगी विनाशकारी युद्ध से उबर ही रहे थे, जिससे वे एक दूसरे से संदेह करते थे और शत्रुतापूर्ण भी बन गए थे। ऐसे में कोई तो चाहिए था, जो उन सबको इकट्ठा करता। इस तरह, नाटो में अमेरिका की भूमिका अस्थायी सहायक से स्थायी रक्षक में बदल गई। लेकिन 1960 के दशक तक यह साफ हो गया कि अमेरिकी सेना जल्दी वापस नहीं जाएगी। एक बार जब वाशिंगटन को एहसास हो गया कि वह वहां से निकल नहीं सकता, तो उसने फैसले लेने शुरू कर दिए। पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के सुरक्षा सलाहकार मैकजॉर्ज बंडी ने 1962 में कहा, 'हमें नेतृत्व की कीमत चुकानी होगी। इसके बदले हमें कुछ फायदे हो सकते हैं।'

इसका मतलब अमेरिकी फर्मों के लिए आकर्षक रक्षा अनुबंध थे, जो यूरोप में अपनी बड़ी उपस्थिति बनाए रखने के लिए शक्तिशाली वित्तीय प्रोत्साहन बन गए। अमेरिकी सैन्य उद्योग यूरोप की निर्भरता से लाभ कमाता है। वर्ष 2022-23 में यूरोपीय संघ के देशों द्वारा खरीदे गए सैन्य उपकरणों का लगभग 63 प्रतिशत अमेरिका से आया था। शीत युद्ध के अंत में यूरोपीय लोगों ने खुद को अमेरिकी सैन्य शक्ति से दूर करने की कोशिश की। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। नतीजतन आज यूरोप में नाटो के सदस्यों की रक्षा के लिए आवश्यक सैनिकों और उपकरणों को तैनात करने की क्षमता का अभाव है, खासकर जब बात वायु रक्षा, खुफिया और निगरानी जैसी विशेष इकाइयों की हो। सौभाग्य से कुछ यूरोपीय नेता इस मामले को उतनी ही तत्परता से ले रहे हैं, जितने की जरूरत है।

नाटो की खरीद योजना अमेरिकी हथियार निर्माताओं पर निर्भर है, जो यूरोपीय आयोग द्वारा मार्च में शुरू की गई नई यूरोपीय रक्षा औद्योगिक रणनीति के खिलाफ है। एक बार फिर, यूरोपीय देशों को एकजुट करने की जरूरत है। दोनों संस्थानों को एक मत होने की सख्त जरूरत है। अगर वे ऐसा करते हैं, तो यह यूरोप की अपनी रक्षा में मदद करने की क्षमता निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। अतीत में अमेरिकियों ने खतरा महसूस कर यूरोपीय रक्षा उद्योग के निर्माण के प्रयास को विफल कर दिया होगा। लेकिन आज अमेरिकी खुद अपने औद्योगिक रक्षा उत्पादन को बढ़ाने के लिए जूझ रहे हैं। जैसा कि जनरल आइजनहावर ने सपना देखा था, आज यूरोपीय लोग अपनी रक्षा के लिए आगे आ रहे हैं, तो अमेरिका को राह का रोड़ा नहीं बनना चाहिए।

©The New York Times 2024

जीवन धारा

जीन डे साल्जमैन

अगर हम जीवन की खूबसूरती और इसकी चुनौतियों को गहराई से महसूस नहीं करते, तो जीवन का कोई मतलब नहीं है। हम हमेशा कहीं पहुंचने का सपना देखते हैं, ताकि वहां हमेशा के लिए रह सकें।

हम हमेशा कहीं पहुंचने का सपना देखते हैं

यह समझना मुश्किल है कि सचेत प्रयास के बिना कुछ भी संभव नहीं है। सचेत प्रयास के लिए दिव्य प्रकृति चाहिए। अकेले निम्न प्रकृति मुझे चेतना की ओर नहीं ले जा सकती। यह अंधी होती है। लेकिन जब मैं जाग्रत होता हूं, तो मुझे मालूम होता है कि मैं एक दिव्य जगत से संबंध रखता हूं और यह सचेत प्रयास के कारण ही होता है। मैं वास्तव में सचेत तभी होता हूं, जब अपनी सारी संभावनाओं को खुला रखता हूं। केवल सचेत प्रयास का ही मूल्य होता है। विचारों का अपना एक गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होना चाहिए; क्योंकि यह यहां-वहां नहीं हो सकता है। हमें इस गुरुत्वाकर्षण केंद्र को ढूंढ़ना होगा। यही बात शरीर के साथ भी लागू होती है, यदि वह केंद्रित नहीं है, तो कोई भी गतिविधि नहीं होगी।

यही बात भावनाओं के साथ है। ये गतिविधियां हमें एक गुरुत्वाकर्षण केंद्र से दूसरे गुरुत्वाकर्षण केंद्र तक जाने के लिए तैयार की गई हैं। यह बदलाव ही है, जो स्थितियों का निर्माण करता है। हाव-भाव, हरकतें ही महत्वपूर्ण हैं, न कि मनोभाव। हमारे पास तीन तरह की शक्तियां होती हैं-शरीर, मन और भावना की। जब तक ये एक साथ, समान रूप से विकसित और सामंजस्यपूर्ण नहीं होंगे, तब तक दिव्य शक्ति के साथ स्थिर संबंध नहीं बनाया जा सकता। हम जो भी कार्य करते हैं, उसमें सब कुछ उस संबंध को बनाने की तैयारी है। यही हमारे कार्य का उद्देश्य है। दिव्य शक्ति शरीर के स्तर तक आना तो चाहती है, पर जब तक कार्य नहीं किया जाता, तब तक आ नहीं सकती। कार्य करके ही आप अपने उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं और ब्रह्मांडीय जीवन में भागीदारी कर सकते हैं। यही हमारे जीवन को महत्व और अर्थ प्रदान कर सकता है। हर दृश्यमान गति के पीछे एक अन्य गति होती है, जो दिखाई नहीं देती, लेकिन बहुत मजबूत होती है और जिस पर बाहरी गति निर्भर करती है। यदि यह आंतरिक गति इतनी बलवान न होती, तो बाहरी गति कोई कार्य नहीं कर पाती। चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है, तो छलांग लगानी पड़ेगी। सचेत होने के लिए हमें वह सब कुछ छोड़ देना चाहिए, जो ज्ञात है। वास्तव में जानना एक ऐसी अवस्था है, जिसमें सब कुछ देखा, समझा और अनुभव किया जाता है, क्योंकि यह अगले क्षण में यह कार्य करने में असमर्थ होता है और बेकार समझकर छोड़ दिया जाता है। कोई भी विचार स्थायी नहीं होता; जो दिखाई देता है, उसे गायब होना ही पड़ता है। गायब होना उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना कि दिखाई देना। आज मैं क्या समझता हूं, और मुझे क्या समझने की जरूरत है? यह मेरी मौजूदगी की स्थिति पर निर्भर करता है। बिना जाग्रत हुए यह दिखावा करना बेतुका है कि मैं काम करना चाहता हूं। अभी इस धरती को हमारे काम की जरूरत है। अगर हम जीवन की खूबसूरती और इसकी चुनौतियों को गहराई से महसूस नहीं करते, तो जीवन का कोई मतलब नहीं है। हम हमेशा कहीं पहुंचने का सपना देखते हैं, ताकि वहां हमेशा के लिए रह सकें। फिर भी स्थायित्व केवल गति में ही पाई जा सकती है।

वास्तविकता का स्वाद

सूत्र

जीवन में काम करने के हमारे प्रयास सबसे पहले यह पता लगाने के लिए हैं कि हम अपनी उच्चतम संभावनाओं से कितने दूर हैं। हमारे काम के केंद्र में अधिक वास्तविक तरीके से जीने की इच्छा होनी चाहिए। वास्तविकता का स्वाद लिए बिना खुद को पुष्ट करने से हम या तो एक अचेतन गुलाम हो सकते हैं या एक सचेत सेवक।

दूसरा पहलू

फ्रेंच गुयाना के समुद्र तट पर पेंटेड लेडी प्रजाति की तितलियों के समूह को देखकर कीटविज्ञानी ने किया उनकी यात्रा पर शोध।

जब तितलियों ने महासागर पार किया

अक्तूबर, 2013 की एक सुबह को कीटविज्ञानी जेरर्ड ट्लावेरा ने अजीब चीज देखी। उन्होंने पेंटेड लेडी प्रजाति की तितलियों के समूह को फ्रेंच गुयाना के समुद्रतट पर देखा। तितलियों की यह प्रजाति दुनिया में सबसे ज्यादा देखी जाती है। पर दक्षिण अमेरिका में वे नहीं दिखती थीं। इसके बावजूद वे इस महादेश के पूर्वी तट पर रेत पर सुस्ता रही थीं। उन तितलियों की दशा देखकर ट्लावेरा को समझने में देर नहीं लगी कि लंबा सफर तय करने के बाद ये तितलियां सुस्ता रही हैं।

कीट-पतंग और तितलियां लंबी दूरी तय करने में माहिर होती हैं। वे यूरोप से सब-सहारा अफ्रीका तक 9,000 मील की दूरी तय करती हैं। लेकिन ट्लावेरा की जिज्ञासा थी कि लेडी पेंटेड तितलियों ने क्या 2,600 मील तक फैले अटलांटिक महासागर को पार किया था, जिस दौरान कहीं रुकने या विश्राम करने की गुंजाइश नहीं थी। कीट-पतंगों की लंबी दूरी के सफर को ट्रैक कर पाना आसान नहीं है। रेडियो ट्रैकिंग डिवाइस जैसे उपकरणों से छोटे आकार के कीट-पतंगों की गतिविधियों की सटीक माप-जोख संभव नहीं है। ऐसे में, कीटविज्ञानियों को इनके आवागमन की गतिविधियों को मापने के लिए वैज्ञानिक अनुमानों और नागरिक-विज्ञानियों के निरीक्षण पर निर्भर रहना पड़ता है। 'हम तितलियों को अक्सर मंडराते, फिर गायब हो जाते देखते हैं। लेकिन हम इसके आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते', ट्लावेरा कहते हैं।

मोनिक ब्रूइलेटी

क्या लेडी पेंटेड तितलियों ने 2,600 मील तक फैले अटलांटिक महासागर को पार किया था? वैज्ञानिक अनुमानों और नागरिक-विज्ञानियों के निरीक्षण ने इसका पता लगाया।

फूलों के पराग के डीएनए को परखने के लिए ट्लावेरा ने वर्ष 2018 में जेनेटिक सीक्वेंसिंग टूल का आविष्कार किया। तितलियां जब फूलों से मधु चूसती हैं, तब पराग के कण उनके शरीर पर चिपके रहते हैं। इस टूल के सहारे उन्होंने पता करने की कोशिश की कि तितलियों ने किन फूलों से मधु चूसा है। पिछले दिनों *नेचर कम्युनिकेशन जर्नल* में प्रकाशित एक अध्ययन में ट्लावेरा और उनकी टीम ने साबित कर दिया कि फ्रेंच गुयाना के समुद्र तट पर आराम करतीं तितलियों ने सचमुच अटलांटिक महासागर पार किया था। उनके निष्कर्ष का आधार यह था कि आराम करतीं तितलियों के शरीर पर पराग के जो कण चिपके थे, वे उन फूलों के थे, जो पश्चिमी अफ्रीका के देशों में पाए जाते हैं। ये फूल अगस्त से नवंबर के बीच खिलते हैं, जो उन तितलियों के यात्रा अभियान के अनुरूप था। कीट-पतंगों का पृथ्वी में सबसे बड़ा प्रवासन है। 35 खरब कीट-पतंग अकेले दक्षिणी इंग्लैंड से सालाना प्रवास करते हैं। इस लिहाज से देखें, तो इनके प्रवासन का वैश्विक स्तर पर बड़ा भारी असर पड़ता है।

तितलियां जब फूलों से मधु चूसती हैं, तब पराग के कण उनके शरीर पर चिपके रहते हैं। ट्लावेरा की टीम ने साबित कर दिया कि फ्रेंच गुयाना के समुद्र तट पर आराम करतीं तितलियों ने सचमुच अटलांटिक महासागर पार किया था।

©The New York Times 2024

आंकड़े

चीन से व्यापार

पिछले 20 वर्षों में भारत के साथ व्यापार में चीन की हिस्सेदारी घटी है। इन वर्षों में करीब चार से पांच फीसदी की कमी आई है।

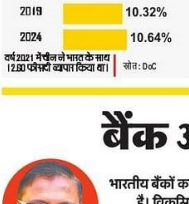

वर्ष 2021 में चीन ने भारत के साथ 12.50 फीसदी व्यापार किया था। स्रोत : DoC

मनु ने प्रियव्रत को भू-मंडल की रक्षा के लिए कहा, तो उन्होंने सोचा कि ऐसे तो भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद ब्रह्मा ने उन्हें उपदेश दिया।

ब्रह्मा ने प्रियव्रत को समझाया

अंतर्यात्रा
संकलित

मनु ने अपने पुत्र प्रियव्रत को भू-मंडल की रक्षा के कार्य के लिए नियुक्त किया। पर प्रियव्रत को नारद जी ने भगवान की भक्ति का उपदेश दिया था। प्रियव्रत भू-मंडल की रक्षा के पिता के आदेश की अवहेलना तो नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने सोचा कि यदि राजकाज में लग गया, तो फिर भगवान का भजन कैसे करूंगा?

प्रियव्रत के अंदर यही विचार चल रहे थे। इसी दौरान ब्रह्मा जी कई ऋषियों के साथ पृथ्वी लोक पर आए और उसी स्थान पर पहुंच गए, जहां प्रियव्रत को नारद जी ने उपदेश दिया था। ब्रह्मा जी को देखकर सभी ने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा प्रियव्रत! मैं तुम्हें जो कुछ कहूंगा, उसे श्रीहरि की आज्ञा समझो, क्योंकि भगवान शंकर, तुम्हारे पिता मनु, तुम्हारे गुरु देवर्षि नारद और मैं उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करते हैं।

उन्होंने प्रियव्रत को समझाया कि जंगल में रहकर भी तुम लोगों से नहीं बच सकते हो, इसलिए पहले गृहस्थ आश्रम का पालन करो। इसके बाद धीरे-धीरे विषय त्यागकर वानप्रस्थ में चले जाना। ब्रह्मा जी के समझाने के बाद प्रियव्रत ने विश्वकर्मा नामक प्रजापति की बर्हिष्मती नाम की कन्या से विवाह किया। उनसे उनको दस पुत्र और एक कन्या हुई। करीब ग्यारह करोड़ वर्ष तक राज्यसुख भोगने के बाद प्रियव्रत अपना राज्य पुत्रों में बांटकर घर-परिवार छोड़कर अपने गुरु नारद के बताए मार्ग पर भगवान की भक्ति में लीन हो गए।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 01 मार्च, 1956

बजट : सूती कपड़ों और खाद्य तेलों पर टैक्स बढ़ा

बड़ी आमदनी वालों पर इन्कम टैक्स भी बढ़ा
इनकम टैक्स रिजिस्ट्री व तार की दरें भी बढ़ाई गईं
नए 1,13,500 के स्लैब में 1.21 करोड़ का पता
सिगरेट व बीड़ियों का कुछ हल्का, पेट्रोल डीजल का महंगा

भारत सरकार के 1956-57 के बजट में 390 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है। वित्तमंत्री चिंतामणि देशमुख ने अपने कार्यकाल का छठा बजट पेश करते हुए सूती कपड़ों और खाद्य तेलों पर टैक्स बढ़ा दिया।

बैंक अपनी भूमिका निभा रहे हैं

भारतीय बैंकों का प्रदर्शन एशियाई बैंकों की तुलना में काफी अच्छा रहा है। विकसित भारत की कहानी में वे अपना योगदान दे रहे हैं।

सतीश सिंह — आर्थिक

नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद देशवासियों की विकास के मोर्चे पर और भी बेहतरी आने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। पिछले दो कार्यकाल में उनकी सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत संरचना, ऊर्जा, सेवा आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए। सबसे कारगर कदम आर्थिक और बैंकिंग क्षेत्र में उठाए गए। 2014 से 2023 के दौरान भारत आर्थिक रूप से विश्व में मजबूत देश बनकर उभरा है।

उम्मीद है कि भारत 2027 में पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था, 2030 में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 2047 में एक विकसित देश बन सकता है। 1947 से 2007 तक भारत की जीडीपी 10 खरब डॉलर की हुई और 2014 में बढ़कर 20 खरब डॉलर की हो गई और 2019 में 30 खरब डॉलर की। 2014 में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की दसवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई थी, जबकि

2019 में यानी सिर्फ पांच वर्षों के अंदर यह दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई।

वित्त वर्ष 2023-24 की मार्च तिमाही में 7.8 फीसदी की दर से जीडीपी में वृद्धि हुई। समग्र रूप से 2023-24 में विकास दर 8.2 फीसदी रही। *'द इंडियन इकनॉमी : ए रिव्यू'* रिपोर्ट के अनुसार, 2024-25 में लगातार चौथे साल भारत की जीडीपी वृद्धि दर सात प्रतिशत से अधिक रह सकती है, जबकि अभी दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर करीब तीन फीसदी है। 2023 में भारत में बेरोजगारी दर 8.7 प्रतिशत रही थी। चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है, इसलिए 2027 तक बेरोजगारी दर के आठ प्रतिशत से कम रहने का अनुमान है। भारत में मुद्रास्फीति दर 2023 में 5.5 प्रतिशत रही है, जबकि 2022 में यह 6.7 प्रतिशत रही थी। मई 2024 में खुदरा महंगाई दर 4.75 प्रतिशत रही। वहीं, 2024 से 2027 के दौरान इसके क्रमशः 4.6, 4.1, 4.1 और 4.0 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इस आधार पर कहा जा सकता है, भारतीय अर्थव्यवस्था आसानी से 2027 तक 50 खरब डॉलर की बन सकती है।

'द इंडियन इकनॉमी : ए रिव्यू' रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार के आर्थिक सुधारों की वजह से ही भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकी है। भारत की जीडीपी 2030 तक सात प्रतिशत की दर से आगे बढ़ सकती है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ग्लोबल ने भी भारत के वित्तीय क्षेत्र में आई मजबूती की पुष्टि की है। एसएंडपी ग्लोबल ने अपनी ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 की रिपोर्ट 'न्यू रिस्क, न्यू प्लेबुक' में कहा कि भारत की नॉमिनल जीडीपी 2022 में 35 खरब डॉलर से बढ़कर 2030 तक 73 खरब डॉलर हो जाएगी। हाल के महीनों में भारतीय बैंकों का प्रदर्शन एशिया में अपने समकक्ष बैंकों की तुलना में सबसे अच्छा रहा है। देश के तीन बड़े बैंकों, भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने 2023 में दुनिया के शीर्ष 50 बैंकों की सूची में अपनी जगह बनाई है। एसएंडपी ग्लोबल की रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में बैंकों की संपत्ति 50.50 प्रतिशत बढ़कर 1.51 लाख करोड़ डॉलर हो गई है। एसएंडपी ग्लोबल के मुताबिक, हाल के महीनों में भारतीय बैंकों द्वारा दिए जा रहे कर्ज में तेज वृद्धि हुई है। 29 दिसंबर, 2023 तक यह 15.6 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई थी, जो एक साल पहले 14.9 प्रतिशत थी। 31 मार्च, 2024 को सरकारी बैंकों का संचयी लाभ 1.4 लाख करोड़ रुपये के स्तर को पार कर गया, जोकि पिछले साल की तुलना में 35 प्रतिशत अधिक है। 2023-24 में सभी बैंकों का शुद्ध फंसा कर्ज (एनपीए) भी घटकर 1.70 प्रतिशत के स्तर से भी नीचे आ गया।

विकसित देश बनने के कुछ मानक हैं। इस क्रम में भारत में औद्योगीकरण, शिक्षा, आधारभूत संरचना, यंत्रीकरण, डिजिटलाइजेशन, स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय का कामकाज फिर से निर्मला सीतारमण के हाथों में है। इसलिए, सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक की नीतियां और उठाए जाने वाले कदम आगामी समय में भी भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय बैंकों के अनुकूल रहेंगे। लिहाजा, देशवासी चाहते हैं कि नया बजट अर्थव्यवस्था और बैंकिंग क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाए।

edit@amarujala.com